JANSATTA, Kolkata, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(10.50)cms X (10.58)cms.

## सिफारिशों पर आठ सप्ताह में मांगी रपट, मानवाधिकार आयोग ने कहा

# संदेशखाली में हुआ था मानवाधिकारों का उल्लंघन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में अत्याचार की कई घटनाओं को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में की गई लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

आयोग ने अपनी रपट में यह भी कहा कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया, जिसके कारण लोगों ने शिकायतें दर्ज कराने से परहेज किया। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रपट मांगी है। इसमें कहा गया है, 'आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोकसेवक की लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

बयान में कहा गया है कि इस रपट को सूचना के व्यापक प्रसार के लिए एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गई जांच की रपट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है और उनसे इन मामलों में की गई कार्रवाई की रपट मांगी है। एनएचआरसी की रपट में कहा गया है कि कथित आरोपियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक बना दिया। इसमें कहा गया है कि आतंक का यह माहौल न केवल उत्पीड़न का चक्र बनाता है, बल्कि पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण बनाने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, ताकि चुप्पी की बेड़ियां तोड़कर वे आजाद हो सकें। उसने यह भी कहा कि डर का माहौल न केवल पीड़ितों पर असर डालता है, बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है, जो इन आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता का उत्पीड़न लगातार देखते हैं।

मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लिया था, जिनमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में एक राजनीतिक व्यक्ति के स्थानीय गिरोह ने निर्दोष और गरीब महिलाओं को प्रताड़ित किया और उनका यौन उत्पीड़न किया। उसने कहा था कि जब स्थानीय प्रशासन अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में असफल रहा तो स्थानीय ग्रामीणों ने पिछले कुछ दिनों से विभिन्न गुंडों और असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दी गई आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

*आयोग* ने अपनी रपट में यह भी कहा कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया, जिसके कारण लोगों ने शिकायतें दर्ज कराने से परहेज किया। *एनएचआरसी* ने एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रपट मांगी है। *इसमें* कहा गया है, 'आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोकसेवक की लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

NAVBHARAT TIMES, Lucknow, 14.4.2024
Page No. 13, Size:(9.02)cms X (8.10)cms.

विचारधारा पर हमला करता रहा है।

# NHRC ने कहा, संदेशखाली में डर से शिकायतें दर्ज नहीं हुईं

■ भाषा, नई दिल्ली

■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर जांच की

**राष्ट्रीय मानवाधिकार** आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में वहां पर आयोग ने अत्याचार की कई घटनाओं को चिह्नित किया। कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बदला लेने के डर और ताकत की वजह से लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई। NHRC ने शनिवार को कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और हर सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ हफ्ते के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने 21 फरवरी को मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लिया था जिनमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में, एक राजनीतिक व्यक्ति के समर्थकों ने महिलाओं को प्रताड़ित कर उनका यौन उत्पीड़न किया।

HINDU, Kochi, 14.4.2024
Page No. 13, Size:(4.39)cms X (6.43)cms.

# NHRC flags 'violation' of human rights in Sandeshkhali

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the National Human Rights Commission (NHRC) has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. The NHRC, in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances. The panel has sought an action taken report within eight weeks from the government of West Bengal, the NHRC said. PTI

HINDU, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 9, Size:(4.33)cms X (6.27)cms.

# 'Inquiry points to 'violation' of human rights in Sandeshkhali'

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the National Human Rights Commission (NHRC) has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. The NHRC, in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances. The panel has sought an action taken report within eight weeks from the government of West Bengal, the NHRC said. PTI

PIONEER, Hyderabad, 14.4.2024
Page No. 5, Size:(18.44)cms X (13.77)cms.

# 'Spot inquiry points to 'violation' of human rights'

PNS ■ NEW DELHI

## Sandeshkhali incident

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the NHRC has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents.

The National Human Rights Commission (NHRC), in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances.

The rights panel has made several recommendations and sought an action taken report (ATR) within eight weeks on each of the recommendations made therein from the government of West Bengal, the NHRC said in a statement on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The report has been uploaded on the NHRC website for "wider dissemination of information," the statement said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person".

As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

RASHTRIYA SAHARA, Varanasi, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(19.79)cms X (20.61)cms.

# संदेशखालि में मौके पर जांच से मानवाधिकारों के 'उल्लंघन' का पता चला

**नई दिल्ली (भाषा)।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखालि मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में 'अत्याचार की कई घटनाओं' को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 'प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया' जिसने लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने से रोका। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की है और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है, 'आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया

- **मानवाधिकार आयोग ने जांच रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी**

ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।' आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गई जांच की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कथित आरोपी व्यक्तियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया' और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें 'न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक' बना दिया। उसने यह भी कहा कि 'डर का माहौल' न केवल पीड़ितों पर असर डालता है बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी 'नकारात्मक असर' डालता है जो लगातार इन कथित आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता के उत्पीड़न को देखते है।

PIONEER, Bhopal, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(35.11)cms X (14.87)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date".

The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

HINDU, Chennai, 14.4.2024
Page No. 9, Size:(4.39)cms X (6.43)cms.

# NHRC flags 'violation' of human rights in Sandeshkhali

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the National Human Rights Commission (NHRC) has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. The NHRC, in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances. The panel has sought an action taken report within eight weeks from the government of West Bengal, the NHRC said. PTI

PIONEER, Lucknow, 14.4.2024
Page No. 5, Size:(35.11)cms X (15.13)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE ■**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has

observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date".

The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

HINDU, Bengaluru, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(4.39)cms X (6.43)cms.

# NHRC flags 'violation' of human rights in Sandeshkhali

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the National Human Rights Commission (NHRC) has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. The NHRC, in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances. The panel has sought an action taken report within eight weeks from the government of West Bengal, the NHRC said. PTI

PIONEER, Vijayawada, 14.4.2024
Page No. 5, Size:(17.44)cms X (13.36)cms.

# 'Spot inquiry points to 'violation' of human rights'

PNS ■ NEW DELHI

## Sandeshkhali incident

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the NHRC has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents.

The National Human Rights Commission (NHRC), in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances.

The rights panel has made several recommendations and sought an action taken report (ATR) within eight weeks on each of the recommendations made therein from the government of West Bengal, the NHRC said in a statement on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The report has been uploaded on the NHRC website for "wider dissemination of information," the statement said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person".

As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

DAINIK JAGRAN, Ranchi, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(2.58)cms X (7.22)cms.

# बंगाल के संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं।

DAINIK JAGRAN, Muradabad, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(5.37)cms X (10.48)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

**बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, बंगाल सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट**

जाब्यू, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

DAINIK JAGRAN, Shimla, 14.4.2024
Page No. 8, Size:(13.77)cms X (7.14)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

- बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं।

## आयोग की सिफारिशें

कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए

- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- यौन शोषण पीडि.तों को परामर्श और पुनर्वास मिले
- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी हो
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन हो
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा किए जाए
- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाया जाए
- सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाएं
- संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त हो।

INDIAN EXPRESS, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(8.76)cms X (13.85)cms.

# 'Gangrapes at TMC office': NHRC submits report on Sandeshkhali

## Police told victims to compromise with perpetrators: Report

**RAVIK BHATTACHARYA**
KOLKATA, APRIL 13

WOMEN ALLEGEDLY gangraped at a Trinamool Congress (TMC) office, victims told by police to reach a compromise with perpetrators, young girls sent away from the village to keep them safe — the National Human Rights Commission (NHRC) has made grave allegations in its inquiry report on the Sandeshkhali incident.

The report was prepared by the rights body after it took suo motu cognisance of the allegations, and is based on a visit to the West Bengal village and conversations with alleged victims. It has been submitted to the Chief Secretary and DGP of West Bengal to submit an action-taken report, with a copy marked to the Central Bureau of Investigation (CBI).

The TMC called the NHRC a "frontal organisation" of the BJP and said the report has been prepared at the party office.

The report lists Shibu Prasad Hazra, Uttam Sardar and Amir Ali Gazi, close associates of suspended TMC strongman Sheikh Shahjahan, as the main accused. The three, as well as Shahjahan, are currently under arrest.

Shahjahan first made headlines in the beginning of January when an Enforcement Directorate (ED) team, which had gone to conduct searches at his residence, came under attack by his supporters. He went on the run, and a month later, protests erupted in

CONTINUED ON PAGE 2

## • NHRC submits Sandeshkhali report

Sandeshkhali, with women residents alleging his associates had been sexually harassing them for years. The women said they felt confident to speak since his influence had waned.

After 55 days on the run, Shahjahan was arrested by the Bengal police on February 29. The probe into complaints has been handed to the CBI, on the directions of the Calcutta High Court.

States the NHRC report: "One of the women disclosed before the NHRC team that about a year back, she was raped two-three times by Hazra and Sardar. Even now, she is not willing to report the rape to the police out of fear of these accused persons and social stigma. She disclosed the incident to her husband, who went to the party office. But he was beaten up by the accused and, out of fear, he went to Bengaluru to earn a livelihood."

"Another woman disclosed before the NHRC team that in the winter of 2022-2023, her husband was forcefully picked up by associates of the accused and made to work in the cold till 2 am. When she went to the party office looking for him, she was touched inappropriately... After 3-4 days, she was called to the party office and gangraped by Hazra and Gazi. The next day, she went to the police station, where she was advised to go to the accused and compromise. After the arrival of the National Commission of Women, she was able to get her case registered against the accused after a gap of more than a year," the report states.

"One of the victims revealed that to safeguard her adolescent girls due to the unsafe environment for young women and girls, she had to send them to live with relatives in another location. It has also been brought to the notice of the team that many more (families) have sent their young girls to other places for their safety," the report states.

"Almost every victim has told the NHRC team that the police did not respond to their complaints against Hazra, Sardar, and their associates. Shockingly, they were advised to approach the accused or their patron Shahjahan directly and seek a compromise," it states.

It further states that women were called to the TMC office by the accused "on the pretext of party meetings and meetings of self-help groups".

"The young and good-looking women were specifically targeted. They were taken inside the room at TMC office at Sandeshkhali and were sexually exploited/gangraped. Other women were engaged in work such as making food, cleaning the office and cleaning the ponds, etc," the report states, adding that the women refrained from reporting the events due to the fear of TMC leaders and social stigma.

When contacted, TMC state general secretary Kunal Ghosh said over the phone: "The report has basically been written in the BJP party office. Such organisations have now become frontal organisations of the BJP. We don't believe in such reports."

Bengal's minister of state for health and family welfare, Chandrima Bhattacharya, said she "will not comment until I have seen the report".

DAINIK JAGRAN, Siliguri, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(13.68)cms X (8.61)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन

## प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट सुधार को सिफारिशें

- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
- कहा-अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ

**आयोग की सिफारिशें**

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं व लड़कियों के मामले की जांच हो
- मामले में गवाहों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- क्षेत्र में यौन शोषण के शिकार पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास का इंतजाम हो
- जिनकी भूमि पर कब्जे किए गए हैं उनके मालिकों को भूमि वापस की जाए
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पीड़ितों से मिलीं शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाए
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन हो
- क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं
- जिस भूमि पर निर्माण किया गया है उसे पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाएं
- सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार और विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाएं
- स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त हो।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी। आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं।

INDIAN EXPRESS, Ahmedabad, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(9.46)cms X (14.83)cms.

# 'Gangrapes at TMC office': NHRC submits report on Sandeshkhali

## Police told victims to compromise with perpetrators: Report

RAVIK BHATTACHARYA
KOLKATA, APRIL 13

WOMEN ALLEGEDLY gangraped at a Trinamool Congress (TMC) office, victims told by police to reach a compromise with perpetrators, young girls sent away from the village to keep them safe — the National Human Rights Commission (NHRC) has made grave allegations in its inquiry report on the Sandeshkhali incident.

The report was prepared by the rights body after it took suo motu cognisance of the allegations, and is based on a visit to the West Bengal village and conversations with alleged victims. It has been submitted to the Chief Secretary and DGP of West Bengal to submit an action-taken report, with a copy marked to the Central Bureau of Investigation (CBI).

The TMC called the NHRC a "frontal organisation" of the BJP and said the report has been prepared at the party office.

The report lists Shibu Prasad Hazra, Uttam Sardar and Amir Ali Gazi, close associates of suspended TMC strongman Sheikh Shahjahan, as the main accused. The three, as well as Shahjahan, are currently under arrest.

Shahjahan first made headlines in the beginning of January when an Enforcement Directorate (ED) team, which had gone to conduct searches at his residence, came under attack by his supporters. He went on the run, and a month later, protests erupted in

CONTINUED ON PAGE 2

## • NHRC submits Sandeshkhali report

Sandeshkhali, with women residents alleging his associates had been sexually harassing them for years. The women said they felt confident to speak since his influence had waned.

After 55 days on the run, Shahjahan was arrested by the Bengal police on February 29. The probe into complaints has been handed to the CBI, on the directions of the Calcutta High Court.

States the NHRC report: "One of the women disclosed before the NHRC team that about a year back, she was raped two-three times by Hazra and Sardar. Even now, she is not willing to report the rape to the police out of fear of these accused persons and social stigma. She disclosed the incident to her husband, who went to the party office. But he was beaten up by the accused and, out of fear, he went to Bengaluru to earn a livelihood."

"Another woman disclosed before the NHRC team that in the winter of 2022-2023, her husband was forcefully picked up by associates of the accused and made to work in the cold till 2 am. When she went to the party office looking for him, she was touched inappropriately... After 3-4 days, she was called to the party office and gangraped by Hazra and Gazi. The next day, she went to the police station, where she was advised to go to the accused and compromise. After the arrival of the National Commission of Women, she was able to get her case registered against the accused after a gap of more than a year," the report states.

"One of the victims revealed that to safeguard her adolescent girls due to the unsafe environment for young women and girls, she had to send them to live with relatives in another location. It has also been brought to the notice of the team that many more (families) have sent their young girls to other places for their safety," the report states.

"Almost every victim has told the NHRC team that the police did not respond to their complaints against Hazra, Sardar, and their associates. Shockingly, they were advised to approach the accused or their patron Shahjahan directly and seek a compromise," it states.

It further states that women were called to the TMC office by the accused "on the pretext of party meetings and meetings of self-help groups".

"The young and good-looking women were specifically targeted. They were taken inside the room at TMC office at Sandeshkhali and were sexually exploited/gangraped. Other women were engaged in work such as making food, cleaning the office and cleaning the ponds, etc," the report states, adding that the women refrained from reporting the events due to the fear of TMC leaders and social stigma.

When contacted, TMC state general secretary Kunal Ghosh said over the phone: "The report has basically been written in the BJP party office. Such organisations have now become frontal organisations of the BJP. We don't believe in such reports."

Bengal's minister of state for health and family welfare, Chandrima Bhattacharya, said she "will not comment until I have seen the report".

DAINIK JAGRAN, Jammu, 14.4.2024
Page No. 10, Size:(16.58)cms X (6.97)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा।

एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

National Human Rights Commission

- बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं।

### आयोग की सिफारिशें

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- यौन शोषण पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास मिले
- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी हो
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन हो
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा किए जाए
- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाया जाए
- सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाए
- संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त हो।

TIMES OF INDIA, Ahmedabad, 14.4.2024
Page No. 10, Size:(21.62)cms X (4.50)cms.

# Sandeshkhali case points to human rights violations: NHRC

Ambika.Pandit@timesgroup.com

**New Delhi:** National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, the NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

The NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. The commission sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

The NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include — "investigation of missing girls and women from Sandehskhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System."

The commission has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

TIMES OF INDIA, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 16, Size:(7.69)cms X (13.49)cms.

# Several instances of atrocities on victims in Sandeshkhali: NHRC

Ambika.Pandit@timesgroup.com

**New Delhi:** National Human Rights Commission's spot inquiry into Sandeshkhali violence has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. NHRC has recommended an impartial investigation by central agencies.

Noting that the Calcutta high court is already hearing the Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of the HC to intervene in the matter.

As per observations in the report based on a spot visit between Feb 23 and 25, "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims.

It has recommended appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include "investigation of missing girls and women from Sandeshkhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counselling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners." It has also sought an action taken re-

## SEEKS CENTRAL PROBE

port on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

According to the report, "Villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances they were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali region."

The NHRC statement also mentioned the inquiry team interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date".

DAINIK JAGRAN, Chandigarh, 14.4.2024
Page No. 10, Size:(8.18)cms X (9.13)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन

## इलाके का दौरा करने के बाद मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें

**रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट**

### आयोग की सिफारिशें

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- यौन शोषण पीडितों को परामर्श और पुनर्वास मिले, भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी हो

जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं।

NAV-BHARAT, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 10, Size:(4.89)cms X (7.75)cms.

# अत्याचार की हदें पार संदेशखाली में

## NHRC की जांच रिपोर्ट में उजागर

■ दिल्ली, एजेंसियां. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी स्पॉट जांच रिपोर्ट में बंगाल के संदेशखाली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कई मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को उजागर किया है. आयोग की जांच में

पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट में मानवाधिकारों का उल्लंघन का जिक्र भी किया गया है. आयोग ने अपनी ये जांच रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेज दी है. पीड़ित ग्रामीणों को हमले, धमकी, यौन शोषण, भूमि पर कब्जा और जबरन बिना पैसे के काम करना पड़ा. इन परिस्थितियों के कारण उन्हें संदेशखाली या राज्य से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा. डर के माहौल से पीड़ितों के बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव. एनएचआरसी ने मीडिया में आईं खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था. फरवरी में एनएचआरसी की एक टीम प संदेशखाली पहुंची थी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में तथ्य जुटाने के लिए ग्रामीणों से बात की थी. संदेशखाली में बड़ी संख्या में लोगों ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर 'जमीन हड़पने व यौन उत्पीड़न' का आरोप लगाया है.

DAINIK JAGRAN, Ranchi, 14.4.2024
Page No. 2, Size:(8.07)cms X (6.44)cms.

# मानवाधिकार आयोग ने किरणी मौत मामले में लिया संज्ञान

## बिरहोर बस्ती को बिना बसाय ही शुरू कर दिया था खनन कार्य

**आयोग ने हजारीबाग की डीसी से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा, मंटू सोनी ने की थी शिकायत**

राज्य ब्यूरो. जागरण ● रांची : हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में कोयला खनन स्थल के समीप बीमारी से हुई नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामला दर्ज कर संज्ञान ले लिया है। आयोग ने इस पूरे प्रकरण में हजारीबाग की डीसी नैंसी सहाय से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर इससे संबंधित रिपोर्ट देने को कहा है। किरणी बिरहोर की मौत का मामला सामाजिक कार्यकर्ता मंटू सोनी ने उठाया था और इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की थी।

मंटू सोनी ने अपनी शिकायत में लिखा था कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के महज कुछ दूरी पर लुप्तप्राय आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की एक बस्ती है, जहां एनटीपीसी के माध्यम से खनन कार्य किया जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव से ही नाबालिग किरणी बिरहोर बीमार चल रही थी। विगत 28 फरवरी को किरणी की मौत हो गई। मंटू सोनी ने आयोग से आग्रह किया है कि बिरहोर बस्ती को बिना बसाए खनन कार्य करने व किरणी बिरहोर की मौत के जिम्मेवार लोगों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जाय।

DAINIK JAGRAN, Agra, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(5.37)cms X (10.48)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

**बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, बंगाल सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट**

जाब्यू, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

DAINIK JAGRAN, Patna, 14.4.2024
Page No. 16, Size:(13.77)cms X (6.98)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन

## बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।

### एनएचआरसी की रिपोर्ट में सिफारिशें

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- यौन शोषण पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास मिले
- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी हो
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो

### ईडी का दावा, संदेशखाली के सांसद-विधायक तय करता था शाहजहां शेख

राज्य ब्यूरो, कोलकाता ● जागरण : संदेशखाली में शाहजहां शेख तय करता था कि इलाके से सांसद-विधायक कौन होगा? वह जो कहता था, वही होता था। ईडी ने शनिवार को बैंक शाल कोर्ट में यह दावा किया। संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले के मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिवक्ता ने कहा कि शाहजहां ने बयान दिया है कि संदेशखाली में वह जो तय करता था, वही होता था। उसकी बात अंतिम होती थी। तृणमूल का शीर्ष नेतृत्व भी उसके कहे अनुसार चलता था। दूसरी तरफ शाहजहां के अधिवक्ता ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उस पर दबाव डालकर बयान लिखवाया है।

DAINIK JAGRAN, Dehradun, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(10.98)cms X (9.70)cms.

# बंगाल के संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी। आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं।

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- यौन शोषण पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास मिले
- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी हो
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन हो
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा किए जाए
- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाया जाए
- सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाएं
- संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त हो।

JANSATTA, Lucknow, 14.4.2024
Page No. 13, Size:(15.57)cms X (17.67)cms.

# मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

मुंबई के विरार इलाके में जलमल शोधन संयंत्र की सफाई करते समय हुई चार लोगों की मौत की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से आयोग ने चार हफ्ते के भीतर इस घटना के बारे में विस्तृत रपट मांगी है। घटना की मीडिया में आई खबर का खुद संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है।

खबर के मुताबिक यह संयंत्र विरार की एक निजी रिहायशी कालोनी में स्थित है। सफाई के दौरान इन मजदूरों ने सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए थे। यह चारों करीब बीस साल के नौजवान थे। ये सभी मुंबई के वसई इलाके के रहने वाले थे। आयोग ने इस मामले में उस ठेकेदार की लापरवाही मानी है, जिसके पास ये चारों मजदूर काम कर रहे थे। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि उसे ऐसे खतरनाक सफाई कार्यों के दौरान सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। यह दुर्घटना दस अप्रैल को हुई। चारों को एक अस्पताल में ले जाया गया।

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 14.4.2024
Page No. 13, Size:(2.58)cms X (8.88)cms.

# संदेशखाली में हुआ था मानवाधिकारों का उल्लंघन : एनएचआरसी

जाब्यू, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा।

AMAR UJALA, Dehradun, 14.4.2024
Page No. 10, Size:(5.23)cms X (6.80)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

DAINIK JAGRAN, Kanpur, 14.4.2024
Page No. 17, Size:(5.29)cms X (9.92)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

- बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(13.40)cms X (2.26)cms.

# NHRC notice to state, DGP over death of 4 sewage workers

**New Delhi:** The NHRC has sent a notice to the government and the police chief over reports of death of four people while they were cleaning a sewage treatment plant without any protective gear in Mumbai. The commission said it has sought a report, which should include the status of the implementation of the Supreme Court guidelines and NHRC advisory about the hazardous cleaning, within four weeks. The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report that four persons, died of suffocation after inhaling toxic gases while cleaning a private sewage treatment plant in a residential township in Virar area".

DECCAN HERALD, Bengaluru, 14.4.2024
Page No. 2, Size:(17.04)cms X (23.26)cms.

# Sandeshkhali spot inquiry shows 'violation' of human rights: NHRC

NEW DELHI, DHNS

**Directives to chief secy**

- Reinstating trust in rule of law
- Confidence in authorities
- Counselling, rehabilitation of victims of sexual offences
- Return of the land to legitimate owners
- Probe cases of missing women/girls

> This climate of terror not only perpetuates the cycle of abuse but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to break free from the shackles of silence.
> - **National Human Rights Commission**

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday said its spot enquiry in West Bengal's Sandeshkhali has revealed "several instances of atrocities inflicted upon the victims", which "clearly demonstrate" that there was a violation of human rights due to negligence of the administration.

It has asked the West Bengal Chief Secretary to submit an Action Taken Report within eight weeks on each of the recommendations made by it, which includes reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities, counselling and rehabilitation of victims of sexual offences, return of the land to the legitimate owners and investigation of cases of missing women/girls from Sandeshkhali.

According to the report prepared by NHRC's investigation team, the atmosphere in Sandeshkhali due to the "atrocities by the alleged accused" rendered the victims silent and reluctant to seek justice.

The villagers and victims who faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali, NHRC stated in its report, adding that the allegations of denial of benefits of state and Union government's schemes such as old age pension, MGNREGA and public distribution system are of a deep concern.

"The pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier, preventing these individuals from voicing their grievances. This climate of terror not only perpetuates the cycle of abuse but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to break free from the shackles of silence," the NHRC said.

The NHRC stated that its investigation team found that there is a "need to uproot the fear of these persons (accused) from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride".

"It is the duty of the district authorities being arms of a welfare state to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general and victims in particular so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints," it said.

AMAR UJALA, Chandigarh, 14.4.2024
Page No. 12, Size:(5.23)cms X (6.87)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(6.91)cms X (18.36)cms.

# NHRC gives Bengal 8 weeks

ARITRA SINGHA / KOLKATA

National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday sent a spot inquiry report to the state government and the state police regarding the Sandeshkhali incident and has asked them to file an action taken report on 12 of its recommendations within eight weeks.

The report was sent after the Calcutta High Court on Wednesday ordered a court monitored CBI probe in all the cases related to Sandeshkhali.

CONTD. ON NATION

## NHRC gives Bengal 8 weeks

Sandeshkhali in North 24 parganas has been in the headlines since January 5 after Enforcement Directorate (ED) officials were beaten up while they went to raid suspended Trinamool Congress (TMC) leader Shahjahan Sheikh's house in connection to the multicrore ration distribution scam.

In February the women of Sandeshkhali started protesting against sexual harassment and land grab by Shahjahan and his associates.

An NHRC delegation led by Vijaya Bharathi Sayani, visited the site on February 23 and stayed there for two days, visited all the spots and had also spoken with the local people.

"The villagers faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour following which several people were forced to leave the village and stayed away from Sandeshkhali," noted the spot inquiry report of NHRC

The NHRC also mentions that several villagers complained that they were not able to cast their votes and unknown 'miscreants' voted on their behalf.

It also spoke of villagers' complaints against the police, saying that the police didn't cooperate with the villagers when they went to complain against Shahjahan and his associates Shibaprasad and Uttam.

Meanwhile, following court's order, CBI has issued a press statement where the central agency has mentioned they have taken steps to comply with the orders of the Court regarding complaints of crime against women and land grabbing in Sandeshkhali.

"In pursuance of the order dated 10.04.2024 passed by the Division bench of Calcutta High Court, CBI has created a dedicated email ID "sandeshkhali@cbi.gov.in" on which the complaints of the persons of Sandeshkhali, North 24 Parganas, West Bengal regarding crime against women and forcible grabbing of land may be lodged," read the statement.

AMAR UJALA, Muradabad, 14.4.2024
Page No. 18, Size:(5.28)cms X (6.88)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

AMAR UJALA, Agra, 14.4.2024
Page No. 14, Size:(5.27)cms X (6.91)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

DAINIK JAGRAN, Bareily, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(5.37)cms X (10.48)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

**बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, बंगाल सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट**

जाब्यू, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

PIONEER, Ranchi, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(34.79)cms X (13.24)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date".

The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

PIONEER, Raipur, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(34.92)cms X (13.56)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date". The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

PIONEER, Dehradun, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(34.91)cms X (12.98)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date".

The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

HAMARA MAHANAGAR, Mumbai, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(7.06)cms X (5.38)cms.

# सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मौत पर NHRC अलर्ट

महानगर संवाददाता

मुंबई

मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई करते समय चार लोगों की हुई मौत पर एनएचआरसी अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। शनिवार को एक बयान जारी कर आयोग ने बताया कि चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

## वसई क्षेत्र के निवासी थे मृतक

बयान के मुताबिक, आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया था कि मुंबई के विरार क्षेत्र में स्थित एक आवासीय टाउनशिप में निजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान जहरीली गैसों से चार लोगों

## राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख को भेजा नोटिस

का दम घुट गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का कथित आरोप है। मृतकों की उम्र करीब 20 साल है। शुरुआती जांच के अनुसार, मृतक वसई क्षेत्र के निवासी थे। मृतक बिना किसी सुरक्षा उपायों के सीवेज प्लांट पहुंचे थे। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

## लोगों में जागरुकता फैलाने की जिम्मेदारी सरकार की

बयान में आयोग ने आगे कहा कि मामले में ठेकेदार की ओर से लापरवाही स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। पीड़ितों को निर्धारित मानदंडों और एनएचआरसी की सलाह का उल्लंघन करते हुए बिना सुरक्षा उपायों के काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों के बीच जागरुकता फैलाएं की बिना सुरक्षा उपकरणों के ऐसे कार्यों को न किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है और उनसे विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

DECCAN CHRONICLE, Chennai, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(4.80)cms X (9.64)cms.

# NHRC probe flags rights violation in Sandeshkhali case

## *Seeks action taken report in 8 weeks*

**New Delhi, April 13:** In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the NHRC has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. The National Human Rights Commission, in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances.

The rights panel has made several recommendations and sought an action taken report within eight weeks on each of the recommendations made therein from the government of West Bengal, the NHRC said in a statement on Saturday. "The commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The report has been uploaded on the NHRC website for "wider dissemination of information," the statement said.

The commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, Bengal for submitting the ATR. The NHRC report made an observation that "atmosphere due to the atrocities by alleged accused persons rendered the victims silent", and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who witness ordeals of their parents at hands of these alleged accused. — *PTI*

DAINIK JAGRAN, Prayagraj, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(5.37)cms X (9.39)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

**बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, बंगाल सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट**

**जाब्यू, नई दिल्ली :** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी।

PIONEER, Chandigarh, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(34.71)cms X (13.56)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date". The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

PIONEER, Bhubaneswar, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(34.57)cms X (12.87)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date". The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

I NEXT, Gorakhpur, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(2.83)cms X (6.50)cms.

# एनएचआरसी ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

**KOLKATA (13 April):** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है. आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं. एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है.

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं.

AMAR UJALA, Varanasi, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(5.19)cms X (6.93)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

AMAR UJALA, Prayagraj, 14.4.2024
Page No. 16, Size:(5.13)cms X (6.88)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

DAINIK JAGRAN, Varanasi, 14.4.2024
Page No. 19, Size:(8.18)cms X (7.50)cms.

# 'संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन'

- बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो ● नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं।

TIMES OF INDIA, Hyderabad, 14.4.2024
Page No. 8, Size:(14.46)cms X (8.70)cms.

# NHRC's spot inquiry at Sandeshkhali finds 'instances of atrocities on victims'

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

**New Delhi**: National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents.

The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, the NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter. As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

**The NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims**

The NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. The commission sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

The NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include — "investigation of missing girls and women from Sandehskhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System."

The commission has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

The inquiry also observes that "allegations of deprivation of the right to vote are serious in nature and undermine the democratic values of the nation."

TIMES OF INDIA, Kochi, 14.4.2024
Page No. 10, Size:(10.78)cms X (11.54)cms.

# Sandeshkhali case points to human rights violations: NHRC

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

File Photo

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt in Sandeshkhali case

New Delhi: National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. NHRC sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include — "investigation of missing girls and women from Sandehskhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System."

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

TIMES OF INDIA, Jaipur, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(14.75)cms X (5.98)cms.

# NHRC's spot inquiry at Sandeshkhali finds 'instances of atrocities on victims'

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

**New Delhi**: National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt in Sandeshkhali case

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims.

PIONEER ( HINDI), Lucknow, 14.4.2024
Page No. 9, Size:(8.63)cms X (12.21)cms.

# संदेशखालि में मौके पर जांच से मानवाधिकारों के उल्लंघन का पता चला : मानवाधिकार आयोग

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखालि मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में अत्याचार की कई घटनाओं को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में की गई लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया , जिसके कारण लोगों ने शिकायतें दर्ज कराने से परहेज किया। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्एक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्वाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है, आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोकसेवक की लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट को सूचना के व्यापक प्रसार के लिए एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गई जांच की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है और उनसे इन मामलों में की गई कार्वाई की रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित आरोपियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक बना दिया।

TIMES OF INDIA, Goa, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(7.62)cms X (13.77)cms.

# Human rights violated in Sandeshkhali: NHRC

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

**New Delhi:** National Human Rights Commission's (NHRC) spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents.

The Commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that the Calcutta High Court is already hearing the Sandeshkhali case, the NHRC will be seeking leave of the HC to intervene in the matter. As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between February 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

The NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. The commission sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

NHRC has sought an action taken report on its recommendations

The NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include - "investigation of missing girls and women from Sandehskhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System (NERS)."

The commission has sought an action taken report on its recommendaitons within eight weeks from the West Bengal govt.

TIMES OF INDIA, Kolkata, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(3.62)cms X (10.99)cms.

# NHRC finds human rights violations in Sandeshkhali

**New Delhi**: National Human Rights Commission's spot inquiry into Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. NHRC has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies, reports **Ambika Pandit**.

Noting that Calcutta HC is already hearing Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter. It has sought an action taken report within eight weeks from Bengal govt.

As per the observations, "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent".

HINDUSTAN TIMES, NOIDA, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(10.99)cms X (15.48)cms.

# Sandeshkhali probe points to human rights violation: NHRC

**Neeraj Chauhan**
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** There were several human rights violations in the troubled Sandeshkhali area of West Bengal, including forced migration, denial of right to vote, sexual exploitation of women and land grabbing, the National Human Rights Commission has said in its spot enquiry report.

The report was sent to West Bengal police and chief secretary and CBI on Friday. HT has reviewed a copy of the report.

"After interacting with the villagers, especially women in Sandeshkhali, the NHRC team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice," said the report.

"The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali or state," the report added.

An investigation team of the NHRC led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with area residents, including women, police officers and doctors, among others.

It found that whenever local residents went with a complaint to the police, they were allegedly advised to approach the accused people, including suspended Trinamool Congress party leader Sheikh Shahjahan, and seek a compromise. Based on these interactions, the human rights body on Friday asked West Bengal chief secretary Bhagwati Prasad Gopalika and DGP Rajeev Kumar to submit an action taken report in the matter in eight weeks while making several recommendations to restore law and order.

**Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh**

"The people who hold portfolios in the NHRC and other such bodies, are usually BJP leaders. They prepare reports favouring the BJP. This has been proven time and again. The same thing has happened this time," said Santanu Sen, TMC MP. No bureaucrats in West Bengal government were willing to comment on the issue.

The riverine island of Sandeshkhali has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate officers arrived to search the home of Shahjahan, a close aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack from an angry mob, leaving three officers injured.

On February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and nearby villages, with groups of residents, led mostly by women, alleging exploitation, land grabbing and sexual harassment at the hands of local TMC leaders, including Shahjahan, his brother Sirajuddin and associates Uttam Sardar and Shibaprasad Hazra.

Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested on February 29 after 55 days on the run. "As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly, who continue to reside in the villages," said the report. The villagers in Sandeshkhali said that "they are denied democratic right to vote", the report said.

"They alleged that during elections, they are prohibited from casting their votes, as supporters of miscreants allegedly cast vote on their behalf," it added. The commission said every victim told its team that "the police do not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates".

"Shockingly, they were advised to approach the alleged accused or their alleged patron Sheikh Shahjahan, and seek a compromise," the report said. "The people have seen what has happened in Sandeshkhali. The high court ordered a CBI probe. This corroborates the NHRC report. It is immaterial what political parties say," said BJP spokesman Samik Bhattacharya.

AMAR UJALA, Panipat, 14.4.2024
Page No. 12, Size:(3.00)cms X (6.83)cms.

# मानवाधिकार आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

फाइल फोटो

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

HINDUSTAN TIMES, Gurgaon, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(10.99)cms X (15.48)cms.

# Sandeshkhali probe points to human rights violation: NHRC

**Neeraj Chauhan**
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** There were several human rights violations in the troubled Sandeshkhali area of West Bengal, including forced migration, denial of right to vote, sexual exploitation of women and land grabbing, the National Human Rights Commission has said in its spot enquiry report.

The report was sent to West Bengal police and chief secretary and CBI on Friday. HT has reviewed a copy of the report.

"After interacting with the villagers, especially women in Sandeshkhali, the NHRC team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice," said the report.

"The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali or state," the report added.

An investigation team of the NHRC led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with area residents, including women, police officers and doctors, among others.

It found that whenever local residents went with a complaint to the police, they were allegedly advised to approach the accused people, including suspended Trinamool Congress party leader Sheikh Shahjahan, and seek a compromise. Based on these interactions, the human rights body on Friday asked West Bengal chief secretary Bhagwati Prasad Gopalika and DGP Rajeev Kumar to submit an action taken report in the matter in eight weeks while making several recommendations to restore law and order.

**Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh**

"The people who hold portfolios in the NHRC and other such bodies, are usually BJP leaders. They prepare reports favouring the BJP. This has been proven time and again. The same thing has happened this time," said Santanu Sen, TMC MP. No bureaucrats in West Bengal government were willing to comment on the issue.

The riverine island of Sandeshkhali has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate officers arrived to search the home of Shahjahan, a close aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack from an angry mob, leaving three officers injured.

On February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and nearby villages, with groups of residents, led mostly by women, alleging exploitation, land grabbing and sexual harassment at the hands of local TMC leaders, including Shahjahan, his brother Sirajuddin and associates Uttam Sardar and Shibaprasad Hazra.

Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested on February 29 after 55 days on the run. "As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly, who continue to reside in the villages," said the report. The villagers in Sandeshkhali said that "they are denied democratic right to vote", the report said.

"They alleged that during elections, they are prohibited from casting their votes, as supporters of miscreants allegedly cast vote on their behalf," it added. The commission said every victim told its team that "the police do not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates".

"Shockingly, they were advised to approach the alleged accused or their alleged patron Sheikh Shahjahan, and seek a compromise," the report said. "The people have seen what has happened in Sandeshkhali. The high court ordered a CBI probe. This corroborates the NHRC report. It is immaterial what political parties say," said BJP spokesman Samik Bhattacharya.

AMAR UJALA, Bareily, 14.4.2024
Page No. 18, Size:(5.27)cms X (6.77)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

AMAR UJALA, Kanpur, 14.4.2024
Page No. 7, Size:(2.62)cms X (6.83)cms.

# संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन : आयोग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।

TIMES OF INDIA, Chennai, 14.4.2024
Page No. 5, Size:(8.00)cms X (12.34)cms.

# NHRC spot inquiry reveals 'instances of atrocities on victims'

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

**New Delhi:** National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

## SANDESHKHALI CASE

Noting that Calcutta HC is already hearing the Sandeshkhali case, the NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter. As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between February 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

**IN RADAR:** NHRC recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies

The NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. The commission sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints. The NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation.

TIMES OF INDIA, Chandigarh, 14.4.2024
Page No. 8, Size:(11.06)cms X (9.59)cms.

# Sandeshkhali case points to human rights violations: NHRC

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

**New Delhi**: National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt in Sandeshkhali case

NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. NHRC sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include — "investigation of missing girls and women from Sandeshkhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System."

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 14.4.2024
Page No. 7, Size:(10.99)cms X (12.90)cms.

# Sandeshkhali probe points to human rights violation: NHRC

**Neeraj Chauhan**
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** There were several human rights violations in the troubled Sandeshkhali area of West Bengal, including forced migration, denial of right to vote, sexual exploitation of women and land grabbing, the National Human Rights Commission has said in its spot enquiry report.

The report was sent to West Bengal police and chief secretary and CBI on Friday. HT has reviewed a copy of the report.

"After interacting with the villagers, especially women in Sandeshkhali, the NHRC team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice," said the report.

"The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali or state," the report added.

An investigation team of the NHRC led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with

**Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh**

area residents, including women, police officers and doctors, among others.

It found that whenever local residents went with a complaint to the police, they were allegedly advised to approach the accused people, including suspended Trinamool Congress party leader Sheikh Shahjahan, and seek a compromise. Based on these interactions, the human rights body on Friday asked West Bengal chief secretary Bhagwati Prasad Gopalika and DGP Rajeev Kumar to submit an action taken report in the matter in eight weeks while making several recommendations to restore law and order.

"The people who hold portfolios in the NHRC and other such bodies, are usually BJP leaders. They prepare reports favouring the BJP. This has been proven time and again. The same thing has happened this time," said Santanu Sen, TMC MP. No bureaucrats in West Bengal government were willing to comment on the issue.

The riverine island of Sandeshkhali has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate officers arrived to search the home of Shahjahan, a close aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack from an angry mob, leaving three officers injured. On February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and nearby villages, with groups of residents, led mostly by women, alleging exploitation, land grabbing and sexual harassment at the hands of local TMC leaders, including Shahjahan, his brother Sirajuddin and associates Uttam Sardar and Shibaprasad Hazra. Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested on February 29 after 55 days on the run. "As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly, who continue to reside in the villages," said the report.

DAINIK BHASKAR, Bhopal, 14.4.2024
Page No. 19, Size:(9.95)cms X (9.05)cms.

संदेशखली मामले की आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

# मौके पर जांच में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संकेतः NHRC

**नई दिल्ली**|राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली मामले की मौके पर की गई जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें एनएचआरसी ने 'अत्याचार के कई मामलों' की पहचान करने का दावा किया है।

एनएचआरसी पे कहा है कि मौके पर की गई जांच से संकेत मिलता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ता पक्ष से जुड़े होने से स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाए। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि मानवाधिकार आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और पश्चिम बंगाल सरकार से उनमें से प्रत्येक पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने 21 फरवरी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों का स्वतःसंज्ञान लिया था कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में 'निर्दोष और गरीब महिलाओं को एक राजनीतिक व्यक्ति के स्थानीय गिरोह ने परेशान और यौन उत्पीड़न किया है।"

HINDUSTAN TIMES, Lucknow, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(7.33)cms X (14.57)cms.

# Sandeshkhali probe points to human rights violation: NHRC

**Neeraj Chauhan**
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** There were several human rights violations in the troubled Sandeshkhali area of West Bengal, including forced migration, denial of right to vote, sexual exploitation of women and land grabbing, the National Human Rights Commission has said in its spot enquiry report.

The report was sent to West Bengal police and chief secretary and CBI on Friday. HT has reviewed a copy of the report.

"After interacting with the villagers, especially women in Sandeshkhali, the NHRC team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice," said the report.

"The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali or state," the report added. An investigation team of the NHRC led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with area residents, including women, police officers and doctors, among others.

It found that whenever local residents went with a complaint to the police, they were allegedly advised to approach the accused people, including suspended Trinamool Congress party leader Sheikh Shahjahan, and seek a compromise. Based on these interactions, the human rights body on Friday asked West Bengal chief secretary Bhagwati Prasad Gopalika and DGP Rajeev Kumar to submit an action taken report in the matter in eight weeks while making several recommendations to restore law and order.

"The people who hold portfolios in the NHRC and other such bodies, are usually BJP leaders. They prepare reports favouring the BJP. This has been proven time and again. The same thing has happened this time," said Santanu Sen, TMC MP. No bureaucrats in West Bengal government were willing to comment on the issue.

The riverine island of Sandeshkhali has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate officers arrived to search the home of Shahjahan, a close aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack from an angry mob, leaving three officers injured. On February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and nearby villages, with groups of residents, led mostly by women, alleging exploitation, land grabbing and sexual harassment at the hands of local TMC leaders, including Shahjahan, his brother Sirajuddin and associates Uttam Sardar and Shibaprasad Hazra.

**Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh**

Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested on February 29 after 55 days on the run. "As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly, who continue to reside in the villages," said the report. The villagers in Sandeshkhali said that "they are denied democratic right to vote", the report said.

"They alleged that during elections, they are prohibited from casting their votes, as supporters of miscreants allegedly cast vote on their behalf," it added. The commission said every victim told its team that "the police do not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates".

HITAVADA, Nagpur, 14.4.2024
Page No. 2, Size:(20.57)cms X (15.89)cms.

# NHRC issues notice to Mah Govt, DGP over death of 4 workers during sewage cleaning

NEW DELHI, Apr 13 (PTI)

THE National Human Rights Commission (NHRC) has sent a notice to the Maharashtra Government and the state police chief over reports of death of four people while they were cleaning a sewage treatment plant allegedly without any protective gear in Mumbai.

In a statement on Saturday, the NHRC said it has sought a report, which should include the status of the implementation of the Supreme Court guidelines and NHRC advisory about the hazardous cleaning, within four weeks.

The NHRC has taken "suo motu cognizance of a media report that four persons, all aged about 20 years, died of suffocation after inhaling toxic gases while cleaning a private sewage treatment plant in a residential township in Virar area", it said.

According to the Commission, the preliminary investigation has revealed that the workers, all of them residents of Vasai area, had "entered the sewage plant without any safety gear".

The Commission said that the content of the media report, if true, amount to a violation of human rights.

"The negligence on the part of the contractor in the instant case is apparent that the victims were deputed to execute such a hazardous work without any safety precautions, violating the law and the prescribed norms as well as the NHRC advisory," the statement said. It is the duty of the state authorities to spread awareness among the common people about the danger of hazardous cleaning without using safety gears or equipment, the rights body said.

The Commission has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police of Maharashtra seeking a detailed report.

The report should include action taken against the guilty and the status of compensation if any, paid to the next of kin of the deceased, the statement said.

AMRIT VICHAR, Lucknow, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(7.63)cms X (18.67)cms.

# मानवाधिकारों का संदेशखालि में हुआ उल्लंघन : आयोग

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प. बंगाल के संदेशखालि मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में अत्याचार की घटनाओं को चिह्नित किया और कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में की गई लापरवाही से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया, जिससे लोगों ने शिकायतें दर्ज कराने से परहेज किया। एनएचआरसी ने कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और हर सिफारिश पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

AMAR UJALA, Gorakhpur, 14.4.2024
Page No. 18, Size:(5.29)cms X (6.84)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

DAINIK BHASKAR, Surat, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(4.54)cms X (9.78)cms.

संदेशखाली मामला

## जांच में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संकेत मिलेः एनएचआरसी

**नई दिल्ली** | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की मौके पर की गई जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें एनएचआरसी ने 'अत्याचार के कई मामलों' की पहचान का दावा किया है। एनएचआरसी पे कहा है कि मौके पर की गई जांच से संकेत मिलता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ता पक्ष से जुड़े होने से लोग आरोपियों के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाए। एनएचआरसी ने शनिवार को कहा कि मानवाधिकार आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प. बंगाल सरकार से उनमें से प्रत्येक पर 8 हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

Amar Ujala

# Sandeshkhali: 'संदेशखाली में मानवाधिकारों का उल्लंघन, लोगों को डरा-धमका कर रखा गया', NHRC ने रिपोर्ट में दावा

https://www.amarujala.com/india-news/sandeshkhali-spot-inquiry-points-to-violation-of-human-rights-says-nhrc-2024-04-13

संदेशखाली में हिंसा मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आई। बताया गया है कि संदेशखाली में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और स्थानीय लोगों को डरा-धमकाकर रखा गया।

विस्तार

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संदेशखाली में लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित ग्रामीणों को हमले, धमकी, यौन शोषण का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों को डरा-धमकाकर रखा गया और इस वजह से उन्हें राज्य छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी द्वारा यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा गया है।

एनएचआरसी ने रिपोर्ट में बताई ये बातें

एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डर की वजह से संदेशखाली के पीड़ित लोग अपनी शिकायत व्यक्त नहीं कर पाए। आयोग द्वारा एक बयान में कहा कि पैनल द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं और पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संदेशखाली में अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, इससे पता चलता है कि सरकार द्वारा लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

‘लगातार अत्याचारों के डर से चुप रहे पीड़ित’

एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार हुए अत्याचारों की वजह से पीड़ित डरे हुए थे। इसलिए वे कुछ कह नहीं पाए और ना ही न्याय मांग पाए। आगे बताया गया है कि पीड़ितों को भय के माहौल से बाहर निकालने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने की तत्काल जरूरत है।

एनएचआरसी ने की ये सिफारिशें

21 फरवरी को, एनएचआरसी ने संदेशखाली को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद आयोग द्वारा इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा मौके पर जांच के लिए एक टीम को तैनात किया गया था। टीम ने संदेशखाली में पुलिस और प्रशासन से भी बातचीत की। एनएचआरसी द्वारा यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के असली हकदारों को भूमि की वापसी और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार देने, संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष दूत नियुक्त करने और लापता महिलाओं के मामलों की जांच करने की भी सिफारिश की गई है।

Navbharat

# NHRC Notice मुंबई में सी वेज की सफाई के दौ रा न चा र श्रमि कों की मौ त, NHRC ने महा रा ष्ट्र सरका र को भेजा नो टि स

https://www.enavabharat.com/state/maharashtra/four-workers-died-while-cleaning-sewage-in-mumbai-nhrc-notice-to-maharashtra-government-899651/

नई दि ल्ली . रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग (एनएचआरसी ) ने मुंबई में कथि त रूप से सुरक्षा उपकरण के बि ना मलजल शो धन संयंत्र की सफा ई करने के दौ रा न हुई चा र लो गों की मौ त की खबर को लेकर महा रा ष्ट्र सरका र एवं रा ज्य के पुलि स प्रमुख को नो टि स भेजा है। आयो ग ने शनि वा र को एक बया न में कहा कि उसने चा र सप्ता ह के अंदर रि पो र्ट मां गी है, जि समें खतरना क सफा ई के बा रे में उच्चतम न्या या लय तथा एनएचआरसी द्वा रा क्रमश: जा री कि ये गये दि शा नि र्देश एवं परा मर्श के क्रि या न्वयन की स्थि ति का ब्यो रा देने को कहा गया है। उसने कहा कि एनएचआरसी ने “वि रा र के एक रि हा यशी क्षेत्र में एक नि जी मलजल शो धन संयंत्र की सफा ई के दौ रा न जहरी ली गैसों के का रण दम घुटने से चा र लो गों की हुई मौ त की खबर का स्वत: संज्ञा न लि या है।” आयो ग के मुताबि क, प्रा थमि क जां च से खुला सा हुआ है

लापरवा ही स्पष्ट है कि पी ड़ि तों को का नून और नि र्धारि त मा नदंडों के सा थ-सा थ एनएचआरसी की सला ह का उल्लंघन करतेहुए बि ना कि सी सुरक्षा एहति यात के ऐसे खतरना क का म को करने के लि ए भेजा गया था ।” उसने कहा कि बि ना सुरक्षा उपकरणों के खतरना क सफा ई के खतरों के बा रे में आम लोगों के बी च जा गरूकता फैला ना रा ज्य प्रशा सन का दा यि त्व है। आयो ग ने महा रा ष्ट्र के मुख्य सचि व एवं पुलि स महा नि देशक को नो टि स जा री कर उनसे वि स्तृत रि पो र्ट मां गी है। उसने कहा कि इस रि पो र्ट में दो षि यों के खि लाफ की गयी का र्रवा ई, मृतकों के परि वा रों को दि ये गए मुआवजे आदि का वि वरण देने को कहा गया है। खबर के अनुसा र,10 अप्रैल को यह घटना घटी थी । (एजेंसी )

Times of India

## Many instances of atrocities on victims in Sandeshkhali: NHRC

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/many-instances-of-atrocities-on-victims-in-sandeshkhali-nhrc/articleshow/109278618.cms

New Delhi: National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. NHRC sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include — "investigation of missing girls and women from Sandeshkhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System."

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

We also published the following articles recently

NHRCs inquiry at Sandeshkhali finds instances of atrocities on victimsNHRC's inquiry into Sandeshkhali uncovers atrocities, recommends impartial investigations, and emphasizes reinstating trust in the rule of law, appointing special rapporteurs, and ensuring witness protection for victims.109276959

CBI launches dedicated email address for complaints by Sandeshkhali victimsCBI's email sandeshkhali@cbi.gov.in for Sandeshkhali victims. High Court orders CBI inquiry on crimes against women. Focus on illegal land conversion. Detailed report, inspection, revenue records examination.109223859

Oppn raises pension issue with NHRCPension distribution controversy intensifies in elections with 33 deaths. NDA accuses officials and YSRC, files complaints with NHRC, ECI. ECI restricts YSRC volunteers. Opposition alleges deliberate delays to instill fear in pensioners.109193515

Prabhat Khabar

## WB News : एनएचआरसी रिपोर्ट में दावा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

WB News : आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गयी जांच की रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है. एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कथित आरोपी व्यक्तियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया" और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें "न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक" बना दिया.

https://www.prabhatkhabar.com/state/west-bengal/nhrc-report-claims-human-rights-violation-in-sandeshkhali-snk

WB News : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली ( Sandeshkhali) मामले की मौके पर पहुंचकर की गयी जांच में 'अत्याचार की कई घटनाओं' को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 'प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया' जिसने लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने से रोका. एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

आयोग ने जांच की रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी

इसमें कहा गया है, 'आयोग की मौके पर पहुंचकर की गयी जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ.' आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गयी जांच की रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है. एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कथित आरोपी व्यक्तियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया" और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें "न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक" बना दिया. उसने यह भी कहा कि 'डर का माहौल' न केवल पीड़ितों पर असर डालता है, बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी 'नकारात्मक असर' डालता है, जो लगातार इन कथित आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता के उत्पीड़न को देखते हैं

आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग

मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आयी उन खबरों पर संज्ञान लिया था जिनमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में, एक राजनीतिक व्यक्ति के समर्थकों द्वारा निर्दोष और गरीब महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है और उनका यौन उत्पीड़न किया गया है. उसने कहा था कि इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ दिन से, स्थानीय ग्रामीणों ने विभिन्न 'गुंडों' और असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दी गयी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. बयान के अनुसार आयोग के दल ने संदेशखाली में पुलिस और प्रशासन से भी बातचीत की व उनसे और जानकारी देने का अनुरोध किया 'लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है.

ABP Live

# Maharashtra: मुंबई में सीवेज की सफाई के दौरान चार लोगों की मौत पर NHRC का एक्शन, महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

https://www.abplive.com/states/maharashtra/mumbai-virar-sewage-plant-death-case-nhrc-sent-notice-to-maharashtra-government-and-police-chief-2664826

Maharashtra News: एनएचआरसी ने विरार के एक रिहायशी क्षेत्र में एक निजी मलजल शोधन संयंत्र की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की हुई मौत की खबर का स्वत: संज्ञान लिया है.

Maharashtra Latest News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मुंबई में कथित रूप से सुरक्षा उपकरण के बिना मलजल शोधन संयंत्र की सफाई करने के दौरान हुई चार लोगों की मौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है. आयोग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें खतरनाक सफाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी की ओर से क्रमश: जारी किये गये दिशानिर्देश के साथ ही परामर्श के क्रियान्वयन की स्थिति का ब्योरा देने को कहा गया है.

आयोग ने कहा कि एनएचआरसी ने "विरार के एक रिहायशी क्षेत्र में एक निजी मलजल शोधन संयंत्र की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की हुई मौत की खबर का स्वत: संज्ञान लिया है." आयोग के मुताबिक, प्राथमिक जांच से खुलासा हुआ है कि वसई क्षेत्र के रहने वाले ये सभी श्रमिक "बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मलजल संयंत्र में गये थे." आयोग ने कहा कि यदि यह खबर सच है, तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है.

'बिना सुरक्षा एहतियात के काम को करने के लिए भेजा गया था'

बयान में कहा गया है, 'इस मामले में ठेकेदार की ओर से लापरवाही स्पष्ट है कि पीड़ितों को कानून और निर्धारित मानदंडों के साथ-साथ एनएचआरसी की सलाह का उल्लंघन करते हुए बिना किसी सुरक्षा एहतियात के ऐसे खतरनाक काम को करने के लिए भेजा गया था.' उसने कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक सफाई के खतरों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना राज्य प्रशासन का दायित्व है.

आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उसने कहा कि इस रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई, मृतकों के परिवारों को दिये गए मुआवजे आदि का विवरण देने को कहा गया है. सूचना के अनुसार, 10 अप्रैल को यह घटना घटी थी.

Business Today

# NHRC sends Sandeshkhali probe report to Bengal govt, ask it to submit its action-taken report

On Friday, NHRC decided to send the inquiry report to the state government and the state police, directing them to file their action-taken reports on the 12 recommendations within eight weeks.

https://www.businesstoday.in/india/story/nhrc-sends-sandeshkhali-probe-report-to-bengal-govt-ask-it-to-submit-its-action-taken-report-425416-2024-04-13

An investigation by the National Human Rights Commission (NHRC) into the Sandeshkhali violence in West Bengal has discovered numerous human rights issues over the past few years. These include sexual exploitation, land seizure, denial of voting rights and a form of forced migration.

On Friday, NHRC decided to send the inquiry report to the state government and the state police, directing them to file their action-taken reports on the 12 recommendations within eight weeks.

The NHRC also plans to approach the Calcutta High Court to participate in the court proceedings.

The report also said when the residents complained to the police, they were told to approach the accused including the Trinamool Congress (TMC) strongman Sheikh Shahjahan, who was arrested by the state police on February 29 after being on the run for 55 days. and seek a compromise.

The residents of Sandeshkhali have also alleged that they were not allowed to vote and that supporters of miscreants cast votes on their behalf. The women residents of the area have narrated several distressing events including instances of harassment, physical torture, and sexual assault.

According to the police station's data, three minor girls and 37 adult women were still 'untraced' in the area between January 1, 2023 and February 25, 2024.

The alleged offences committed in the island village of Sandeshkhali are among the top election issues in Bengal. Prime Minister Narendra Modi and Union home minister Amit Shah have repeatedly referred to the allegations to criticise the TMC, especially on the question of women's safety. Chief minister Mamata Banerjee has said the state government took swift action against the perpetrators and accused the BJP of vendetta politics.

On Wednesday, the Calcutta High Court issued a crucial directive, ordering a court-monitored Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the matter. Recognising the need for all possible assistance, the court emphasises the importance of the state facilitating the investigative process.

Directing the probe agency to file a report on the illegal conversion of agricultural land for pisciculture, the high court said the probe would be monitored by the court.

On April 4, the Calcutta HC slammed the West Bengal government led by Chief Minister Mamata Banerjee over allegations of extortion, land grab, and sexual assault arising from Sandeshkhali.

The West Bengal government was accused of trying to protect Shahjahan Sheikh, a powerful local party leader implicated in the Sandeshkhali case.

Shahjahan Sheikh and his associates faced serious allegations from women in Sandeshkhali, North 24 Parganas, for committing severe abuses and atrocities. Several women on the island accused the TMC leader and his associates of engaging in "land-grabbing and sexual assault" through coercion.

AMAR UJALA, Bhopal, 14.4.2024
Page No. 12, Size:(5.30)cms X (6.87)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

Amar Ujala

# Mumbai: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुई चार मौत पर एनएचआरसी अलर्ट, राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख को भेजा नोटिस

https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-issues-notice-to-maharashtra-govt-and-dgp-amid-death-of-four-workers-during-sewage-cleaning-2024-04-13

सार

देश

बयान के मुताबिक, आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया था कि मुंबई के विरार क्षेत्र में स्थित एक आवासीय टाउनशिप में निजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान जहरीली गैसों से चार लोगों का दम घुट गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई करते समय चार लोगों की हुई मौत पर एनएचआरसी अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। शनिवार को एक बयान जारी कर आयोग ने बताया कि चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

## वसई क्षेत्र के निवासी थे मृतक

बयान के मुताबिक, आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया था कि मुंबई के विरार क्षेत्र में स्थित एक आवासीय टाउनशिप में निजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान जहरीली गैसों से चार लोगों का दम घुट गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का कथित आरोप है। मृतकों की उम्र करीब 20 साल है। शुरुआती जांच के अनुसार, मृतक वसई क्षेत्र के निवासी थे। मृतक बिना किसी सुरक्षा उपायों के सीवेज प्लांट पहुंचे थे। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

## लोगों में जागरुकता फैलाने की जिम्मेदारी सरकार की

बयान में आयोग ने आगे कहा कि मामले में ठेकेदार की ओर से लापरवाही स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। पीड़ितों को निर्धारित मानदंडों और एनएचआरसी की सलाह का उल्लंघन करते हुए बिना सुरक्षा उपायों के काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों के बीच जागरुकता फैलाएं की बिना सुरक्षा उपकरणों के ऐसे कार्यों को न किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है और उनसे विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

Financial Express

# Sandeshkhali: Spot inquiry points to 'violation' of human rights, says NHRC

The National Human Rights Commission (NHRC), in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances.

https://www.financialexpress.com/india-news/sandeshkhali-spot-inquiry-points-to-violation-of-human-rights-says-nhrc/3455924/

In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the NHRC has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents.

The National Human Rights Commission (NHRC), in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances.

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

The rights panel has made several recommendations and sought an action taken report (ATR) within eight weeks on each of the recommendations made therein from the government of West Bengal, the NHRC said in a statement on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The report has been uploaded on the NHRC website for "wider dissemination of information," the statement said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person".

As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

The NHRC team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date", the statement said.

The recommendations given by the NHRC team, include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

Counselling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; impartial investigation of complaints by central agencies; initiating awareness programmes are other recommendations, it said.

Operationalisation of a nationwide emergency response system (NERS); and vocational training and creating employment opportunities have also been recommended.

Reviving the land to make it suitable for agriculture; improving socio-economic indicators and preparing area-specific plans; appointing special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali; and investigating cases of missing women or girls from the area of the police station of Sandeshkhali are among the other recommendations.

The Commission has noted that "this incident is also seized by the High Court of Judicature at Calcutta in WPA No.4011 of 2024. It has decided to seek leave from the High Court to intervene in the matter," the statement said.

India Today

# 'Climate of terror': Human rights body reveals report on Sandeshkhali violence

The National Human Rights Commission said a 'climate of terror' was created in West Bengal's Sandeshkhali by the fear of reprisal among the complainants and the power dynamics at play.

https://www.indiatoday.in/india/story/human-rights-commission-report-sandeshkhali-violence-west-bengal-government-climate-of-terror-2526832-2024-04-14

In Short

Human rights body prepares report into Sandeshkhali violence

Report flags several human rights violations in the village

Report sent to Bengal Chief Secretary and top cop

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday flagged several human rights concerns in its enquiry report over the allegations of sexual harassment raised by the women of West Bengal's Sandeshkhali.

The rights body said that the villagers of Sandeshkhali "faced assault, threats, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour" and a "climate of terror" was created by officials who have been alleged to have worked in connivance with the accused.

The NHRC said its enquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which "clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant".

At the centre of the women's allegations was suspended Trinamool Congress leader Sheikh Shahjahan and his aides. The women spoke up after he went into hiding before his arrest.

The atrocities committed by the accused "rendered the victims silent and intimidated" and the subsequent terror "created reluctance to seek justice" said the NHRC. The residents of Sandeshkhali were forced to seek a livelihood elsewhere due to the situation, it added.

The rights body also pointed out that there are allegations of discrimination/denial of benefits of state/central government schemes by officials in collusion with the accused. It said a climate of terror was created by the fear of reprisal, the power dynamics at play.

It is an urgent need to create a safe and supportive environment for the victims to "break free from the shackles of silence" and to ensure the cycle of abuse no longer exists, said NHRC.

The atmosphere of fear not only affects the victims but also has a negative impact on the growth and health of the children who witness the ordeals of their parents at the hands of the accused, it added.

"The NHRC investigation team found that there is a need to uproot the fear of these people from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride," said the report.

The report further stated that it is the duty of the district authorities to take measures to instil confidence in the residents of the area in general and victims in particular, so that people may come forward and file their complaints.

NHRC'S RECOMMENDATIONS TO BENGAL GOVERNMENT:

Reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities.

Ensuring witness protection and redressal of grievances.

Counseling and rehabilitation of victims of sexual offences.

Return of the land to the legitimate owners.

Impartial investigation of complaints by central agencies.

Initiating awareness programmes.

Operationalisation of Nationwide Emergency Response System (NERS).

Vocational training and creating employment opportunities.

Reviving the land to make it suitable for agriculture.

Improving socioeconomic indicators and preparing area-specific plans.

Appointing Special Rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali.

Investigation of cases of missing women/girls from the area of Sandeshkhali Police Station.

The NHRC had taken suo motu cognisance of the allegations being raised by the women in the village in February. The human rights body has sent its enquiry report to the Chief Secretary and West Bengal DGP (police).

It has also sought an Action Taken Report from the Chief Secretary within the next eight weeks.

ABP Live

## Spot inquiry points to 'violation' of human rights, says NHRC

https://news.abplive.com/news/india/sandeshkhali-violence-nhrc-finds-breach-of-human-rights-seeks-bengal-govt-s-action-taken-report-1679732

The National Human Rights Commission (NHRC), which is investigating the Sandeshkhali violence, has found a blatant breach of human rights due to "negligence" in the prevention of atrocities. According to news agency PTI, the NHRC stated in its report that people's "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier" that kept them from speaking out about their grievances.

The NHRC also said in a statement on Saturday that it has made several recommendations and asked the West Bengal government to submit an action taken report (ATR) on each of the recommendations within eight weeks.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," the NHRC report stated.

The report has been uploaded on the website of NHRC for "wider dissemination of information," the statement further added.

To submit the ATR, the Commission has forwarded its spot inquiry report to the West Bengal DGP and chief secretary.

The NHRC report observed that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror compel them "reluctant to seek justice". This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also outlines the dire need to create a safe and conducive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has noted.

The rights panel has also noted that the "atmosphere of fear" has a "negative impact" on the development and well-being of the children who are continuously exposed to their parents' suffering at the hands of these accused parties, in addition to having an effect on the victims.

Media Reports On Sandeshkhali Atrocities

The reports in print and electronic media stating that "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a local gang of a political person" in Sandeshkhali, North 24 Paraganas, were brought to the attention of the NHRC suo motu on February 21.

Due to the local administration's failure to take appropriate legal action against the criminals, the villagers had been protesting for the past few days, demanding that the

"perpetrators of horrific crimes indulged in by various goons and anti-social elements" be held accountable.

Apart from requesting reports from the state government, the Commission, acknowledging the seriousness of the situation, constituted an investigation team for an on-site inquiry, led by one of its members. Additionally, the NHRC team spoke with the administration and police at Sandeshkhali and asked for more information. However, the statement added, "Despite reminders, no reply has been given to date."

The NHRC team recommended "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" in addition to making sure that grievances are addressed and witnesses are protected. "Counselling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; impartial investigation of complaints by central agencies; initiating awareness programmes are other recommendations," it highlighted, according to PTI.

It has also been suggested to operationalise a national emergency response system (NERS) and provide employment opportunities, and vocational training.

The other suggestions included restoring the rightful land owners to allow agriculture, enhancing socio-economic indicators, creating plans tailored to each area, designating special rapporteurs to provide periodic updates on the state of affairs in Sandeshkhali, and looking into any cases of missing women or girls from the Sandeshkhali police station's surrounding area.

jagran.com

# Sandeshkhali Violence: संदेशखाली में हुआ था मानवाधिकार का उल्लंघन, NHRC ने बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

https://www.jagran.com/news/national-human-rights-were-violated-in-sandeshkhali-nhrc-seeks-action-report-from-bengal-government-23696148.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मौके का दौरा कर दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

संदेशखाली में हुआ था मानवाधिकार का उल्लंघन। फाइल फोटो।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मौके का दौरा कर दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

## अत्याचार के कारण पीड़ित हुए खामोश

आरोपितों द्वारा किये गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं और डराने धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमला, धमकी, यौन शोषण, भूमि कब्जा का सामना करना पड़ा और जबरन अवैतनिक श्रम करना पड़ा। इन परिस्थितियों में उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा।

## रिपोर्ट में की गई कई सिफारिशें

आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

## महिलाओं के यौन शोषण के मामले आए सामने

संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आये थे और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा हुई थी। संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार के नेता शेख शाहजहां आरोपी है।

शाहजहां काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में महिलाओं के शोषण और भूमि कब्जा करने के बारे में मीडिया में आयी खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वत: संज्ञान लिया था और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।

आयोग ने संदेशखाली भेजी थी टीम

आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी। आयोग की टीम ने मौके से लौट कर अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि आरोपितों के गिरोह से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किये जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं इससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं। आयोग ने पीड़ितों के पुनर्वास और व्यवस्था में उनका भरोसा कायम करने के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं।

आयोग की सिफारिशें

1- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल करना

2- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच

3- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना

4- यौन शोषण पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास

5- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी

6- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच

7- जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना

8- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन

9- व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा करना

10- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाना

11- सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार करना

12- संदेशखाली की स्थिति पर समय समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त करना

Hindustan Times

# NHRC sends Sandeshkhali probe report to Bengal govt, seeks action-taken report

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-sends-sandeshkhali-probe-report-to-bengal-govt-seeks-action-taken-report-101713004253613.html

On Friday, NHRC sent the inquiry report to the state government and the state police, directing them to file their action-taken reports within 8 weeks

NEW DELHI: An inquiry by the National Human Rights Commission (NHRC) into the Sandeshkhali violence in West Bengal has revealed multiple human rights concerns over the last few years including sexual exploitation, land grabbing, denial of the right to vote and "a kind of forced migration".

On Friday, NHRC decided to send the inquiry report to the state government and the state police, directing them to file their action-taken reports on the 12 recommendations within eight weeks.

The commission, which had taken suo motu cognisance of media reports on the violence in February, also decided to approach the Calcutta high court to intervene in the court proceedings "since NHRC was also inquiring into the complaints of violation of human rights of the victims and its spot enquiry report reveals several instances of atrocities inflicted upon the victims which clearly demonstrate, prima facie, there was violation of human rights due to negligence in prevention of such violation or abatement thereof by the public servant."

The commission's decision comes after the high court on Wednesday ordered the Central Bureau of Investigation (CBI) to probe all allegations levelled by residents of Sandeshkhali since February, and said it will monitor the process.

NHRC has sent a copy of its report to the CBI as well.

The report also said when the residents complained to the police, they were told to approach the accused including the Trinamool Congress (TMC) strongman Sheikh Shahjahan, who was arrested by the state police on February 29 after being on the run for 55 days. and seek a compromise.

HT has reviewed the report.

The riverine island of Sandeshkhali in North 24 Parganas district has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate (ED) officers arrived to search the home of Shahjahan, a close aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack, leaving three officers injured.

But, on February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and other nearby villages, with groups of residents, led mostly by local women, alleging sexual harassment at the hands of local TMC leaders including Shahjahan, his brother

Sirajuddin, and other associates Uttam Hazra and Shibu Sardar, who have since been arrested. Other villages said that Shahjahan and his associates also indulged in land-grab.

An NHRC investigation team led by its member, Vijaya Bharathi Sayani, visited Sandeshkhali from February 23 to 25.

In their report, the team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to the atrocities had rendered the victims silent and reluctant to seek justice. "The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside the Sandeshkhali region or state," said the NHRC spot enquiry report.

"As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly who continue to reside in the villages."

"The decision to migrate is often driven by the pursuit of better economic opportunities and also staying in their hometown could potentially expose them to working for the alleged accused or political parties without wages. This is a kind of forced migration," the report said, adding that this bleak situation painted a vivid picture of economic hardship and exploitation.

The villagers also alleged they were not allowed to cast their votes and "supporters of miscreants allegedly cast vote on their behalf". The report also highlighted cases of land grabbing.

On the role of the police, the report said every victim told the team that "the police do not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates". "Shockingly, they (residents) were advised to approach the alleged accused or their alleged patron Sheikh Shahjahan and seek a compromise instead of receiving the support they sought from the police. The common people have lost faith in the local police," it said.

The report said the women narrated a series of distressing events including instances of harassment, physical torture, and sexual assault. According to the police station's data, three minor girls and 37 adult women were still "untraced" in the area between January 1, 2023 and February 25, 2024.

The state police told the team that 25 cases had been registered after the violence including seven sexual assault cases against Sheikh, Sardar and Hazra. The police have also arrested 24 persons so far.

The alleged offences committed in the island village of Sandeshkhali — around a dozen first information reports have been filed so far — are among the top poll issues in Bengal that sends 42 members to the Lok Sabha. Prime Minister Narendra Modi and Union home minister Amit Shah have repeatedly referred to the allegations to attack the TMC, especially on the question of women's safety. Chief minister Mamata Banerjee has said

the state government took swift action against the perpetrators and accused the BJP of vendetta politics.

Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested by the state police on the orders of the high court on February 29 after 55 days on the run. Although state CID took over the investigation Shahjahan was handed over to CBI under court orders.

Jagran English

# NHRC Flags Human Rights Violations In Sandeshkhali, Seeks 'Action Taken Report' From Govt Within Eight Weeks

https://english.jagran.com/india/nhrc-flags-human-rights-violations-in-sandeshkhali-seeks-action-taken-report-from-govt-within-eight-weeks-10154004

Sandeshkhali Violence: The Human Rights body has undertaken a comprehensive spot inquiry into the Sandeshkhali case, uncovering numerous instances of atrocities that underscore a troubling violation of human rights.

Sandeshkhali Row: The National Human Rights Commission (NHRC) has conducted a spot inquiry into the Sandeshkhali case, flagging "several instances of atrocities" and indicating a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. NHRC, in its report, also observed a pervasive fear of reprisal and power dynamics that acted as barriers to individuals voicing their grievances. The human rights panel made several recommendations and sought an action take report (ATR) from the West Bengal government within eight weeks.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said as quoted by news agency PTI.

The psychological toll of living in constant fear and uncertainty cannot be overstated, and measures must be taken to address these underlying issues and provide support to those affected, the added further.

In response to these findings, the NHRC has put forth a series of recommendations that focus on addressing the root cause of these human rights violations and ensuring the protection and empowerment of the affected communities. These recommendations encompass a wide range of measures, including reinstating trust in the rule of law, implementing witness protection mechanisms, and providing comprehensive counselling and rehabilitation services to victims of sexual offences.

Moreover, the NHRC has emphasised the importance of raising awareness and promoting education on human rights issues to foster a culture of accountability and respect for fundamental rights. Additionally, there is a pressing need to address socio-economic disparities and create opportunities for economic empowerment in the affected communities.

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(3.15)cms X (7.08)cms.

# मलजल शोधन संयंत्र की सफाई के दौरान चार श्रमिकों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब

**नई दिल्ली (भाषा)।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुंबई में कथित रूप से सुरक्षा उपकरण के बिना मलजल शोधन संयंत्र की सफाई करने के दौरान हुई चार लोगों की मौत की खबर को लेकर महाराष्ट्र सरकार एवं राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। आयोग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें खतरनाक सफाई के बारे में उच्चतम न्यायालय तथा एनएचआरसी द्वारा क्रमशः जारी किये गये दिशानिर्देश एवं परामर्श के क्रियान्वयन की स्थिति का ब्योरा देने को कहा गया है।

उसने कहा कि एनएचआरसी ने 'विरार के एक रिहायशी क्षेत्र में एक निजी मलजल शोधन संयंत्र की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की हुई मौत की खबर का स्वतः संज्ञान लिया है।' आयोग के मुताबिक, प्राथमिक जांच से खुलासा हुआ है कि वसई क्षेत्र के रहने वाले ये सभी श्रमिक 'बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मलजल संयंत्र में गये थे।' आयोग ने कहा कि यदि यह खबर सच है, तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है, इस मामले में ठेकेदार की ओर से लापरवाही स्पष्ट है कि पीड़ितों को कानून और निर्धारित मानदंडों के साथ-साथ एनएचआरसी की सलाह का उल्लंघन करते हुए बिना किसी सुरक्षा एहतियात के ऐसे खतरनाक काम को करने के लिए भेजा गया था।'

उसने कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक सफाई के खतरों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना राज्य प्रशासन का दायित्व है। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उसने कहा कि इस रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मृतकों के परिवारों को दिये गए मुआवजे आदि का विवरण देने को कहा गया है।

Deccan Herald

# NHRC flags human rights violations in Bengal's troubled Sandeshkhali

https://www.deccanherald.com/india/west-bengal/nhrc-flags-human-rights-violations-in-bengals-troubled-sandeshkhali-2976681

According to the report prepared by NHRC's investigation team, the atmosphere in Sandeshkhali due to the 'atrocities by the alleged accused' rendered the victims silent and reluctant to seek justice.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday said its spot enquiry in West Bengal's Sandeshkhali has revealed "several instances of atrocities inflicted upon the victims", which "clearly demonstrate" that there was a violation of human rights due to negligence of the administration.

It has asked the West Bengal Chief Secretary to submit an Action Taken Report within eight weeks on each of the recommendations made by it, which includes reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities, counselling and rehabilitation of victims of sexual offences, return of the land to the legitimate owners and investigation of cases of missing women/girls from Sandeshkhali.

According to the report prepared by NHRC's investigation team, the atmosphere in Sandeshkhali due to the "atrocities by the alleged accused" rendered the victims silent and reluctant to seek justice.

The villagers and victims who faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour were compelled to seek livelihood outside the Sandeshkhali, it said adding the allegations of denial of benefits of state and union government schemes such as old age pension, MGNREGA and Public Distribution System are of deep concern.

"The pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier, preventing these individuals from voicing their grievances. This climate of terror not only perpetuates the cycle of abuse but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to break free from the shackles of silence," the NHRC said.

It said its investigation team found that there is a "need to uproot the fear of these persons (accused) from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

"It is the duty of the district authorities being arms of a welfare state to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general and victims in particular so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints," it said.

INDIAN EXPRESS, Delhi, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(7.99)cms X (5.36)cms.

# 'Gangrapes at TMC office': NHRC submits report on Sandeshkhali

## Police told victims to compromise with perpetrators: Report

**RAVIK BHATTACHARYA**
KOLKATA, APRIL 13

WOMEN ALLEGEDLY gangraped at a Trinamool Congress (TMC) office, victims told by police to reach a compromise with perpetrators, young girls sent away from the village to keep them safe — the National Human Rights Commission (NHRC) has made grave allegations in its inquiry report on the Sandeshkhali incident.

The report was prepared by the rights body after it took suo motu cognisance of the allegations, and is based on a visit to the West Bengal village and conversations with alleged victims. It has been submitted to the Chief Secretary and DGP of West Bengal to submit an action-taken report, with a copy marked to the Central Bureau of Investigation (CBI).

The TMC called the NHRC a "frontal organisation" of the BJP and said the report has been prepared at the party office.

The report lists Shibu Prasad Hazra, Uttam Sardar and Amir Ali Gazi, close associates of suspended TMC strongman Sheikh Shahjahan, as the main accused. The three, as well as Shahjahan, are currently under arrest.

Shahjahan first made headlines in the beginning of January when an Enforcement Directorate (ED) team, which had gone to conduct searches at his residence, came under attack by his supporters. He went on the run, and a month later, protests erupted in

CONTINUED ON PAGE 2

INDIAN EXPRESS, Delhi, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(7.99)cms X (5.36)cms.

# • NHRC submits Sandeshkhali report

Sandeshkhali, with women residents alleging his associates had been sexually harassing them for years. The women said they felt confident to speak since his influence had waned.

After 55 days on the run, Shahjahan was arrested by the Bengal police on February 29. The probe into complaints has been handed to the CBI, on the directions of the Calcutta High Court.

States the NHRC report: "One of the women disclosed before the NHRC team that about a year back, she was raped two-three times by Hazra and Sardar. Even now, she is not willing to report the rape to the police out of fear of these accused persons and social stigma. She disclosed the incident to her husband, who went to the party office. But he was beaten up by the accused and, out of fear, he went to Bengaluru to earn a livelihood."

"Another woman disclosed before the NHRC team that in the winter of 2022-2023, her husband was forcefully picked up by associates of the accused and made to work in the cold till 2 am. When she went to the party office looking for him, she was touched inappropriately... After 3-4 days, she was called to the party office and gangraped by Hazra and Gazi. The next day, she went to the police station, where she was advised to go to the accused and compromise. After the arrival of the National Commission of Women, she was able to get her case registered against the accused after a gap of more than a year," the report states.

"One of the victims revealed that to safeguard her adolescent girls due to the unsafe environment for young women and girls, she had to send them to live with relatives in another location. It has also been brought to the notice of the team that many more (families) have sent their young girls to other places for their safety," the report states.

"Almost every victim has told the NHRC team that the police did not respond to their complaints against Hazra, Sardar, and their associates. Shockingly, they were advised to approach the accused or their patron Shahjahan directly and seek a compromise," it states.

It further states that women were called to the TMC office by the accused "on the pretext of party meetings and meetings of self-help groups".

"The young and good-looking women were specifically targeted. They were taken inside the room at TMC office at Sandeshkhali and were sexually exploited/gangraped. Other women were engaged in work such as making food, cleaning the office and cleaning the ponds, etc," the report states, adding that the women refrained from reporting the events due to the fear of TMC leaders and social stigma.

When contacted, TMC state general secretary Kunal Ghosh said over the phone: "The report has basically been written in the BJP party office. Such organisations have now become frontal organisations of the BJP. We don't believe in such reports."

Bengal's minister of state for health and family welfare, Chandrima Bhattacharya, said she "will not comment until I have seen the report".

TIMES OF INDIA, Delhi, 14.4.2024
Page No. 19, Size:(11.06)cms X (9.59)cms.

# Many instances of atrocities on victims in Sandeshkhali: NHRC

**Ambika.Pandit**
@timesgroup.com

**New Delhi**: National Human Rights Commission's spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed "several instances of atrocities on victims" that prima facie show that there was violation of human rights due to "negligence in prevention" of these incidents. The commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.

Noting that Calcutta high court is already hearing Sandeshkhali case, NHRC will be seeking leave of HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between Feb 23-25 "the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent" and the "intimidation" and "terror created" made them "reluctant to seek justice".

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt in Sandeshkhali case

NHRC emphasised on the need to "reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities" and "uproot the fear" of these accused persons from the hearts of the victims. NHRC sought district authorities instill confidence so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include — "investigation of missing girls and women from Sandeshkhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System."

NHRC has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from West Bengal govt.

The Indian Express

# ‘Gangrapes at TMC office’: NHRC submits report on Sandeshkhali

Police told victims to compromise with perpetrators: Report

https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/gangrapes-at-tmc-office-nhrc-submits-report-on-sandeshkhali-9268540/

Women allegedly gangraped at a Trinamool Congress (TMC) office, victims told by police to reach a compromise with perpetrators, young girls sent away from the village to keep them safe — the National Human Rights Commission (NHRC) has made grave allegations in its inquiry report on the Sandeshkhali incident.

The report was prepared by the rights body after it took suo motu cognisance of the allegations, and is based on a visit to the West Bengal village and conversations with alleged victims. It has been submitted to the Chief Secretary and DGP of West Bengal to submit an action-taken report, with a copy marked to the Central Bureau of Investigation (CBI).

The TMC called the NHRC a “frontal organisation” of the BJP and said the report has been prepared at the party office.

The report lists Shibu Prasad Hazra, Uttam Sardar and Amir Ali Gazi, close associates of suspended TMC strongman Sheikh Shahjahan, as the main accused. The three, as well as Shahjahan, are currently under arrest.

Shahjahan first made headlines in the beginning of January when an Enforcement Directorate (ED) team, which had gone to conduct searches at his residence, came under attack by his supporters. He went on the run, and a month later, protests erupted in Sandeshkhali, with women residents alleging his associates had been sexually harassing them for years. The women said they felt confident to speak since his influence had waned.

After 55 days on the run, Shahjahan was arrested by the Bengal police on February 29. The probe into complaints has been handed to the CBI, on the directions of the Calcutta High Court.

States the NHRC report: “One of the women disclosed before the NHRC team that about a year back, she was raped two-three times by Hazra and Sardar. Even now, she is not willing to report the rape to the police out of fear of these accused persons and social stigma. She disclosed the incident to her husband, who went to the party office. But he was beaten up by the accused and, out of fear, he went to Bengaluru to earn a livelihood.”

“Another woman disclosed before the NHRC team that in the winter of 2022-2023, her husband was forcefully picked up by associates of the accused and made to work in the cold till 2 am. When she went to the party office looking for him, she was touched inappropriately… After 3-4 days, she was called to the party office and gangraped by

Hazra and Gazi. The next day, she went to the police station, where she was advised to go to the accused and compromise. After the arrival of the National Commission of Women, she was able to get her case registered against the accused after a gap of more than a year," the report states.

"One of the victims revealed that to safeguard her adolescent girls due to the unsafe environment for young women and girls, she had to send them to live with relatives in another location. It has also been brought to the notice of the team that many more (families) have sent their young girls to other places for their safety," the report states.

"Almost every victim has told the NHRC team that the police did not respond to their complaints against Hazra, Sardar, and their associates. Shockingly, they were advised to approach the accused or their patron Shahjahan directly and seek a compromise," it states.

It further states that women were called to the TMC office by the accused "on the pretext of party meetings and meetings of self-help groups".

"The young and good-looking women were specifically targeted. They were taken inside the room at TMC office at Sandeshkhali and were sexually exploited/gangraped. Other women were engaged in work such as making food, cleaning the office and cleaning the ponds, etc," the report states, adding that the women refrained from reporting the events due to the fear of TMC leaders and social stigma.

When contacted, TMC state general secretary Kunal Ghosh said over the phone: "The report has basically been written in the BJP party office. Such organisations have now become frontal organisations of the BJP. We don't believe in such reports."

Bengal's minister of state for health and family welfare, Chandrima Bhattacharya, said she "will not comment until I have seen the report".

Times of India

# NHRC’s inquiry at Sandeshkhali finds ‘instances of atrocities on victims’

https://timesofindia.indiatimes.com/india/nhrcs-inquiry-at-sandeshkhali-finds-instances-of-atrocities-on-victims/articleshow/109276959.cms

NEW DELHI: National Human Rights Commission’s spot inquiry into the violence in Sandeshkhali case has revealed “several instances of atrocities on victims” that prima facie show that there was violation of human rights due to “negligence in prevention” of these incidents. The Commission has recommended an impartial investigation into the complaints by central agencies.
Noting that the Calcutta High Court is already hearing the Sandeshkhali case, the NHRC will be seeking leave of the HC to intervene in the matter.

As per the observations in the report based on a spot visit by a team led by one of its members from the commission between February 23-25 “the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent” and the “intimidation” and “terror created” made them “reluctant to seek justice”.
The NHRC emphasised on the need to “reinstate trust in the rule of law and confidence in authorities” and “uproot the fear” of these accused persons from the hearts of the victims. The commission highlights the important role that district authorities have going forward in instilling confidence among residents so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints.

The NHRC has recommended the appointment of special rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali. Some of the other recommendations include - “investigation of missing girls and women from Sandehskhali; ensuring witness protection and redressal of grievances; counseling and rehabilitation of victims of sexual offences; return of the land to the legitimate owners; operationalisation of Nationwide Emergency Response System (NERS).”
The enquiry report highlights with much concern that according to data on missing females provided by Police Station Sandeshkhali from January 1,2023 to February 25, as many as 37 young women and 3 minor girls were still untraced. "This number is alarmingly large and a thorough in-depth investigation is required to trace the victims and to ascertain the reasons for their going missing including the angel of human trafficking," the report states. Hence the Commission has recommended that an investigation is necessary into cases of women who have gone missing.
The commission has sought an action taken report on its recommendations within eight weeks from the West Bengal govt.

According to the report the “The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances they were compelled to seek livelihood outside the Sandeshkhali region.”

The inquiry also observes that “allegations of deprivation of the right to vote are serious in nature and undermine the democratic values of the nation.”

The NHRC statement further highlighted that the inquiry team interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date”.

Sheikh Shahjahan - the prime accused facing allegations of land grab and sexual harassment in Sandeshkhali, was arrested on February 29 by the state police. A Trinamool Congress (TMC) leader, Shahjahan, was suspended by the party for six years after his arrest.

On February 21, the NHRC, had taken suo motu cognizance of media reports related to the protests and violence in Sandeshkhali. Besides deciding on sending a team to the spot, the Commission also sought a report from the state government. In response to the NHRC notice the DG & IGP, West Bengal on February 29 revealed that a total of 25 cases were registered among which 7 cases were on complaints of alleged sexual offence against women and 24 accused persons were arrested. The state authorities had said that efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali area was described by the state authorities "to be well under control".

Hindustan Times

# Sandeshkhali probe points to human rights violation: NHRC

https://www.hindustantimes.com/india-news/sandeshkhali-probe-points-to-human-rights-violation-nhrc-101713034442619.html

An NHRC team led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with area residents, including women, among others.

There were several human rights violations in the troubled Sandeshkhali area of West Bengal, including forced migration, denial of the democratic right to vote, sexual exploitation of women and land grabbing, the National Human Rights Commission has said in its spot enquiry report.

The spot report of team, approved by the NHRC was sent to West Bengal police and chief secretary and CBI on Friday. HT has reviewed a copy of the report.

“After interacting with the villagers, especially women in the area of Sandeshkhali, the NHRC team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice,” said the report.

“The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside the Sandeshkhali region or state,” the report added.

An investigation team of the NHRC led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with area residents, including women, police officers and doctors, among others.

It found that whenever local residents went with a complaint to the police, they were allegedly advised to approach the accused people, including suspended Trinamool Congress party leader Sheikh Shahjahan, and seek a compromise.

Based on these interactions, the human rights body on Friday asked West Bengal chief secretary Bhagwati Prasad Gopalika and director general of police Rajeev Kumar to submit an action taken report in the matter within eight weeks while making several recommendations to restore law and order.

“The people who hold portfolios in the NHRC and other such bodies, are usually BJP leaders. They prepare reports favouring the BJP. This has been proved time and again. The same thing has happened this time. It is just a repetition,” said Santanu Sen, TMC MP.

No bureaucrats in West Bengal government were willing to comment on the issue.

The riverine island of Sandeshkhali has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate officers arrived to search the home of Shahjahan, a close

aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack from an angry mob, leaving three officers injured.

On February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and nearby villages, with groups of residents, led mostly by women, alleging exploitation, land grabbing and sexual harassment at the hands of local TMC leaders, including Shahjahan, his brother Sirajuddin and associates Uttam Sardar and Shibaprasad Hazra. Other villages said Shahjahan and his associates also allegedly indulged in grabbing land.

Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested by state police on the orders of the Calcutta high court on February 29 after 55 days on the run. Although state criminal investigation department took over the probe, Shahjahan was handed over to the Central Bureau of Investigation under the high court's orders on March 6.

The Calcutta high court on April 10 asked CBI to investigate all allegations of Sandeshkhali residents since February.

"As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly, who continue to reside in the villages," said the report.

"The decision to migrate is often driven by the pursuit of better economic opportunities and also staying in their home town could potentially expose them to working for the alleged accused or political parties without wages. This is a kind of forced migration," the commission said.

The villagers in Sandeshkhali said that "they are denied democratic right to vote", the report said.

"They alleged that during elections, they are prohibited from casting their votes, as supporters of miscreants allegedly cast vote on their behalf," it added.

The report also highlighted alleged instances of land grabbing, disruption of natural habitats leading to environmental concerns, and safety of witnesses, among other concerns.

The commission said every victim told its team that "the police do not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates".

"Shockingly, they were advised to approach the alleged accused or their alleged patron Sheikh Shahjahan, and seek a compromise instead of receiving the support they sought from the police," the report said. "The common people have lost faith in the local police."

Between January 1, 2023, and February 25, 2024, three minor girls and 37 adult women were "untraced" in the area, according to data from Sandeshkhali police station that was shared with the NHRC team.

Local police, after the violence in February, registered 25 cases, out of which seven are related to sexual offences against Shahjahan, Sardar and Hazra, according to the report. Police have arrested 24 people so far in these cases.

The alleged offences committed in Sandeshkhali are among the top poll issues in the eastern state that sends 42 members to the Lok Sabha.

Prime Minister Narendra Modi and Union home minister Amit Shah have repeatedly referred to the allegations to attack the TMC, especially on the issue of women's safety. Chief minister Mamata Banerjee has said the state government took swift action against the perpetrators and accused the Bharatiya Janata Party of vendetta politics.

"The people have seen what has happened in Sandeshkhali. The high court ordered a CBI probe. This corroborates the NHRC report. It is immaterial what political parties say," said BJP spokesman Samik Bhattacharya.

HINDUSTAN TIMES, Online, 14.4.2024
Page No. 0, Size:(17.86)cms X (25.62)cms.

ANI News

# NHRC issues notice to Maharashtra govt over death of four sewage workers

https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-issues-notice-to-maharashtra-govt-over-death-of-four-sewage-workers20240413224836/#google_vignette

New Delhi [India], April 13 (ANI): Taking cognizance of a media report about the death of four people while cleaning a sewage treatment plant without protective gear in Mumbai, the National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday issued notice to the Maharashtra government calling for a detailed report within four weeks.
NHRC has taken suo motu cognizance of a media report that four persons, all aged about 20 years, died of suffocation after allegedly inhaling toxic gases while cleaning a private sewage treatment plant in a residential township in the Virar area of Mumbai in Maharashtra, according to an official statement from the NHRC.
Reportedly, the preliminary investigation revealed that the workers, all of them residents of the Vasai area, had entered the sewage plant without any safety gear.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of human rights. The negligence on the part of the contractor in the instant case is apparent that the victims were deputed to execute such hazardous work without any safety precautions violating the law and the prescribed norms as well as the NHRC advisory.
It is the duty of the state authorities to spread awareness amongst the common people about the danger of hazardous cleaning without using safety gear/ equipment, the NHRC said in the statement.
Accordingly, the NHRC has issued the notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Maharashtra calling for a detailed report on the matter. It should include action taken against the guilty and the status of compensation if any, paid to the next of kin of the deceased persons.
The Commission would also like to know whether the Apex Court guidelines and NHRC advisory are being complied with by the authorities concerned. The response is expected within four weeks, added the official statement.
According to the media report, carried out on April 10, 2024, all four victims were rushed to a hospital where they were declared dead. The two other workers, who went near the plant to look for them, also complained of uneasiness and needed treatment. (ANI)

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 14.4.2024
Page No. 7, Size:(5.19)cms X (5.33)cms.

# संदेशखालि में मौके पर जांच से मानवाधिकारों के 'उल्लंघन' का पता चला

**नई दिल्ली (भाषा)।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखालि मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में 'अत्याचार की कई घटनाओं' को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 'प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया' जिसने लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने से रोका। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की है और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है, 'आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया

- मानवाधिकार आयोग ने जांच रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी

ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।' आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गई जांच की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कथित आरोपी व्यक्तियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया' और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें 'न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक' बना दिया। उसने यह भी कहा कि 'डर का माहौल' न केवल पीड़ितों पर असर डालता है बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी 'नकारात्मक असर' डालता है जो लगातार इन कथित आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता के उत्पीड़न को देखते हैं।

The Print

# NHRC issues notice to Maha govt, DGP over death of 4 workers during sewage cleaning

https://theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-maha-govt-dgp-over-death-of-4-workers-during-sewage-cleaning/2039600/

New Delhi, Apr 13 (PTI) The NHRC has sent a notice to the Maharashtra government and the state police chief over reports of death of four people while they were cleaning a sewage treatment plant allegedly without any protective gear in Mumbai.

In a statement on Saturday, the National Human Rights Commission said it has sought a report, which should include the status of the implementation of the Supreme Court guidelines and NHRC advisory about the hazardous cleaning, within four weeks.

The NHRC has taken “suo motu cognisance of a media report that four persons, all aged about 20 years, died of suffocation after inhaling toxic gases while cleaning a private sewage treatment plant in a residential township in Virar area,” it said.

According to Commission, the preliminary investigation has revealed that the workers, all of them residents of Vasai area, had “entered the sewage plant without any safety gear.” The Commission said that the content of the media report, if true, amount to a violation of human rights.

“The negligence on the part of the contractor in the instant case is apparent that the victims were deputed to execute such a hazardous work without any safety precautions, violating the law and the prescribed norms as well as the NHRC advisory,” the statement said.

It is the duty of the state authorities to spread awareness among the common people about the danger of hazardous cleaning without using safety gears or equipment, the rights body said.

The Commission has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Maharashtra seeking a detailed report.

The report should include action taken against the guilty and the status of compensation if any, paid to the next of kin of the deceased, the statement said.

According to media reports, carried on April 10, all four youths were rushed to a hospital where they were declared brought dead.

Two other workers, who went near the plant to look for the four, also complained of uneasiness and needed treatment, the reports said. PTI KND VN VN

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

NAVODYA TIMES, Delhi, 14.4.2024
Page No. 9, Size:(15.65)cms X (7.34)cms.

# 'संदेशखालि में मानवाधिकारों के उल्लंघन का चला पता'

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखालि मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में 'अत्याचार की कई घटनाओं' को चिन्हित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 'प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया' जिसने लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने से रोका।

VEER ARJUN, Delhi, 14.4.2024
Page No. 7, Size:(28.57)cms X (14.66)cms.

# संदेशखालि में मौके पर जांच से मानवाधिकारों के उल्लंघन का पता चला : आयोग

नई दिल्ली, (भाषा)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखालि मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में अत्याचार की कई घटनाओं को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया जिसने लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने से रोका। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्वाई रिपोर्ट मांगी है।

इसमें कहा गया है, आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीडतिों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गई जांच की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित आरोपी व्यक्तियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीडतिों को चुप करा दियौ और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुकै बना दिया। उसने यह भी कहा कि डर का माहौल न केवल पीडतिों पर असर डालता है बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है जो लगातार इन कथित आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता के उत्पीड़न को देखते हैं।

मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आयी उन खबरों पर संज्ञान लिया था जिनमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखालि में, एक राजनीतिक व्यक्ति के समर्थकों द्वारा निर्दोष और गरीब महिलाओं को प्रताडति किया गया है और उनका यौन उत्पीड़न किया गया है।

उसने कहा था कि इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ दिन से, स्थानीय ग्रामीणों ने विभिन्न गुंडों और असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दी गई आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्वाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बयान के अनुसार आयोग के दल ने संदेशखालि में पुलिस और प्रशासन से भी बातचीत की तथा उनसे और जानकारी देने का अनुरोध किया लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नही दिया गया है।

The Print

# ‘Women gangraped at TMC office, one asked by cops to compromise’: NHRC’s report on Sandeshkhali

Report names 3 TMC leaders — Shibu Hazra, Uttam Sardar and Amir Ali Ghazi — as accused. All are currently in jail. TMC's Kunal Ghosh dismisses report, says 'NHRC is a BJP cadre'.

https://theprint.in/india/women-gangraped-at-tmc-office-one-asked-by-cops-to-compromise-nhrcs-report-on-sandeshkhali/2039360/

Kolkata: A report released Saturday by the National Human Rights Commission (NHRC) on Sandeshkhali violence highlights cases of alleged gangrape by Trinamool Congress (TMC) leaders inside its party office.

ThePrint has accessed a copy of the NHRC report on Sandeshkhali where at least two women told the team they were “gangraped” by Trinamool leaders but refused to report the incident to the police.

In this report, the NHRC has named TMC leaders Shibu Prasad Hazra, Uttam Sardar, and Amir Ali Ghazi, who allegedly acted under the directions and patronage of party strongman Sheikh Shahjahan.

The 11-page report states that the villagers were initially “reluctant to share their ordeals” out of fear. “However, after building rapport and gaining their confidence, the team was able to make them comfortable and they narrated about the prevailing situation and atrocities committed by the alleged named persons (sic).”

It adds, “Women of the village were called at the TMC Party office by the named alleged accused persons on the pretext of party meeting and meeting of self-help groups. They used to make the women sit in the office late at night and used abusive and filthy language. The young and good-looking women were specifically targeted. They were taken inside the room at TMC office at Sandeshkhali and were sexually exploited/gang raped. Other women were engaged in work such as making food, cleaning the office, and cleaning of the ponds etc. The women were forced to go to the party office whenever called (sic).”

The NHRC, a central organisation, had taken suo motu cognizance of media reports of human rights violation in West Bengal’s Sandeshkhali, a remote village in the Sundarbans, on 21 February.

“One of the women at Majher para disclosed before the NHRC team that about a year back she was raped two-three times by Shibu Prasad Hazra and Uttam Sardar. Even now, she is not willing to report the rape to the police out of fear of these alleged accused persons and social stigma,” the report says.

Uttam Sardar was arrested on 10 February, hours after being suspended by the TMC for six years. TMC similarly suspended Shibu Hazra and Sheikh Shahjahan following their arrests on 18 and 29 February, respectively. Media reports claim Amir Ali Ghazi was arrested shortly after Shahjahan.

The building from where Shibu Hazra allegedly operated from in Sandeshkhali | Sreyashi Dey | ThePrint

In another instance recorded by the NHRC team, a woman from Gholapara disclosed to the NHRC team that in the winter of 2022-2023, she had visited the party office looking for her husband who had been "forcefully" picked up by the associates of the accused.

The report says, "…she was touched inappropriately by the alleged accused persons and they tried to pull up her 'saree'. Anyhow, she could manage to escape. After 3-4 days, she was called in the party office and gangraped by Shibu Prasad Hazra and Amir Ali Ghazi". The next day, when she went to Sandeshkhali Police Station to file a complaint, she was advised "to go to the alleged accused persons and compromise", the report adds.

After a year of the alleged incident, she was able to file a complaint with the police with the help of the National Commission of Women team that visited the village.

The report also states that several women have sent their minor daughters to live with their relatives away from Sandeshkhali for their safety.

In rather critical observations that raised serious allegations against the West Bengal government, the NHRC team recorded fear of reprisal along with power dynamics at play acting as a deterrent for the alleged victims to speak up. "This climate of terror not only perpetuated the cycle of abuse but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to break free from the shackles of silence. The atmosphere of fear not only affects the victims but also has a negative impact on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents in the hands of these alleged accused," says the report.

Data from January 2023 to February 2024 — provided by Sandeshkhali Police Station to the NHRC team — reveals that three minor girls and 37 young-adult women are untraceable as "missing female victims".

The TMC has, meanwhile, dismissed the findings of the report, claiming the NHRC to be a "BJP" cadre. "A party that has no answers for Unnao, Hathras, Bilkis Bano and Manipur should not preach about the dignity of women. The NHRC is a BJP cadre, the party knows it is organisationally weak in Bengal and that's why it uses CBI, ED, NHRC and the rest to try and silence us, the people can see through their lies," said Kunal Ghosh of the TMC to ThePrint.

Apart from sexual harassment, villagers have also made allegations of land grab, discrimination, and denial of benefits from government schemes if they refuse to "comply with the directives" of the accused.

The NHRC has stated in its report that it will seek leave of the Calcutta High Court to intervene in the matter that is being heard by the Chief Justice bench of the HC. It has also served copies of the report to the chief secretary and director general of police (DGP) and sought an action taken report within eight weeks.

NHRC's investigation

For its report, a team of the NHRC, led by Vijaya Bharathi Sayani, comprising Vikram Harimohan Meena, Senior Superintendent of Police; Monia Uppal, Deputy Superintendent of Police; and Inspectors Ratan Sarkar and Arun Tyagi, visited Sandeshkhali between 23 and 25 February and interacted with the residents, police officials, BDO and doctor of the area hospital. The team met the villagers of Majher Para/Colony Para, Patra Para, and Gholapara in Sandeshkhali, and Haldar Para in Jheliakhali to conduct their inquiry.

According to a report dated 26 February, 2024, of Sub Divisional Police Officer, Minakhan, details of which are included in the NHRC report, a total of 25 suo motu cases have been registered, of which seven were of alleged sexual offences against women by Sheikh Shahjahan, Shibu Hazra, Uttam Sardar and their associates. Shahjahan is currently in the custody of the Enforcement Directorate (ED).

NHRC claims in its report that documents and records sought from the officer in-charge (OC) and block development officer (BDO) of Sandeshkhali are still awaited.

NHRC's past reports on West Bengal

This is not the first time that the NHRC has presented a grim report about the state of affairs in West Bengal, bringing discomfort for the ruling TMC government.

After the 2021 Vidhan Sabha elections, the NHRC said West Bengal has "law of ruler" rather than "rule of law", while naming TMC leaders in its final report on alleged post-poll violence submitted to the Calcutta HC on July 13, 2021. The HC ordered a court-monitored CBI probe into the cases that are still being investigated.

Last July, during the Panchayat poll nomination filing period, the NHRC took suo motu cognizance of reports of violence and appointed its director general of investigation as a special human rights observer to conduct an on-site survey of West Bengal in consultation with the State Election Commission to identify sensitive constituencies at risk of violence in the run up to polls.

NHRC deputes its DG (Investigation) as a Special Human Rights Observer to conduct an on the spot survey of West Bengal, in consultation with the State Election Commission, to identify sensitive constituencies prone to violence in the upcoming panchayat polls;

— NHRC India (@India_NHRC) June 11, 2023

This latest report is likely to trigger a fresh political fight between the ruling TMC and the Opposition BJP.

Women, show reports, make up 49 percent of West Bengal's voters. In the 2021, Vidhan Sabha elections, the women primarily supported "didi" (Chief Minister Mamata Banerjee) and cast their ballot for TMC.

In the 2019 Lok Sabha elections, 17 of the state's 42 seats recorded a higher turnout of women than men — of these, TMC won eight, BJP won seven and the Congress two.

With a 9.8 percent increase in fresh women voters between 2021-2024 in West Bengal, as per ECI data, women's issues are likely to dominate the campaigns of political parties this election season.

Prime Minister Narendra Modi has mentioned Sandeshkhali in his public rallies in West Bengal to highlight "atrocities against women" in West Bengal, admonishing the opposition for staying silent over Sandeshkhali reports.

The BJP has nominated Sandeshkhali complainant Rekha Patra as their Lok Sabha candidate in Basirhat constituency. The party faces a stiff challenge from Mamata in West Bengal, where it has set a target of 30 seats.

Speaking to ThePrint, BJP leader and advocate Priyanka Tebriwal said that the party doesn't politicise atrocities against women but said that the Sandeshkhali violence will cost the TMC their women votebank. "The women of West Bengal have understood that there is no point in raising Lakshmir Bhandar (WB govt women welfare scheme) funds when their safety is not guaranteed. The women will vote against Mamata Banerjee and that will be clear in the results," she said.

(Edited by Zinnia Ray Chaudhuri)

JANSATTA, Delhi, 14.4.2024
Page No. 11, Size:(6.44)cms X (5.79)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में अत्याचार की कई घटनाओं को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में की गई लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

आयोग ने अपनी रपट में यह भी कहा कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया, जिसके कारण लोगों ने शिकायतें दर्ज कराने से परहेज किया। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रपट मांगी है। इसमें कहा गया है, 'आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोकसेवक की लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस रपट को सूचना के व्यापक प्रसार के लिए एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

जनसत्ता Sun, 14 April 2024
https://epaper.jansatta.com/c/74905507

JANSATTA, Delhi, 14.4.2024
Page No. 13, Size:(5.41)cms X (6.31)cms.

# मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली 13 अप्रैल (ब्यूरो)।

मुंबई के विरार इलाके में जलमल शोधन संयंत्र की सफाई करते समय हुई चार लोगों की मौत की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से आयोग ने चार हफ्ते के भीतर इस घटना के बारे में विस्तृत रपट मांगी है। घटना की मीडिया में आई खबर का खुद संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है।

खबर के मुताबिक यह संयंत्र विरार की एक निजी रिहायशी कालोनी में स्थित है। सफाई के दौरान इन मजदूरों ने सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए थे। यह चारों करीब बीस साल के नौजवान थे। ये सभी मुंबई के वसई इलाके के रहने वाले थे। आयोग ने इस मामले में उस ठेकेदार की लापरवाही मानी है, जिसके पास ये चारों मजदूर काम कर रहे थे। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि उसे ऐसे खतरनाक सफाई कार्यों के दौरान सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। यह दुर्घटना दस अप्रैल को हुई। चारों को एक अस्पताल में ले जाया गया।

जनसत्ता Sun, 14 April 2024
https://epaper.jansatta.com/c/

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 14.4.2024
Page No. 6, Size:(10.99)cms X (15.48)cms.

# Sandeshkhali probe points to human rights violation: NHRC

**Neeraj Chauhan**
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** There were several human rights violations in the troubled Sandeshkhali area of West Bengal, including forced migration, denial of right to vote, sexual exploitation of women and land grabbing, the National Human Rights Commission has said in its spot enquiry report.

The report was sent to West Bengal police and chief secretary and CBI on Friday. HT has reviewed a copy of the report.

"After interacting with the villagers, especially women in Sandeshkhali, the NHRC team observed that the atmosphere of intimidation, and terror created due to atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice," said the report.

"The villagers/victims faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour, and under the given circumstances, they were compelled to seek livelihood outside Sandeshkhali or state," the report added.

An investigation team of the NHRC led by Vijaya Bharathi Sayani visited Sandeshkhali on February 23-25 and interacted with area residents, including women, police officers and doctors, among others.

It found that whenever local residents went with a complaint to the police, they were allegedly advised to approach the accused people, including suspended Trinamool Congress party leader

**Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh**

Sheikh Shahjahan, and seek a compromise. Based on these interactions, the human rights body on Friday asked West Bengal chief secretary Bhagwati Prasad Gopalika and DGP Rajeev Kumar to submit an action taken report in the matter in eight weeks while making several recommendations to restore law and order.

"The people who hold portfolios in the NHRC and other such bodies, are usually BJP leaders. They prepare reports favouring the BJP. This has been proven time and again. The same thing has happened this time," said Santanu Sen, TMC MP. No bureaucrats in West Bengal government were willing to comment on the issue.

The riverine island of Sandeshkhali has been in the eye of the storm since January 5, when Enforcement Directorate officers arrived to search the home of Shahjahan, a close aide of former minister Jyoti Priya Mallick, who was arrested in October last year in connection with an alleged ration distribution scam. The ED team came under attack from an angry mob, leaving three officers injured.

On February 7, other violent protests began erupting in Sandeshkhali and nearby villages, with groups of residents, led mostly by women, alleging exploitation, land grabbing and sexual harassment at the hands of local TMC leaders, including Shahjahan, his brother Sirajuddin and associates Uttam Sardar and Shibaprasad Hazra.

Shahjahan, a former TMC zila parishad leader, was arrested on February 29 after 55 days on the run. "As per villagers, a significant number of men from the Sandeshkhali area have chosen to seek livelihood in distant places, leaving behind the women, children, and elderly, who continue to reside in the villages," said the report. The villagers in Sandeshkhali said that "they are denied democratic right to vote", the report said.

"They alleged that during elections, they are prohibited from casting their votes, as supporters of miscreants allegedly cast vote on their behalf," it added. The commission said every victim told its team that "the police do not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates".

"Shockingly, they were advised to approach the alleged accused or their alleged patron Sheikh Shahjahan, and seek a compromise," the report said. "The people have seen what has happened in Sandeshkhali. The high court ordered a CBI probe. This corroborates the NHRC report. It is immaterial what political parties say," said BJP spokesman Samik Bhattacharya.

DAINIK JAGRAN, Delhi, 14.4.2024
Page No. 8, Size:(13.78)cms X (7.75)cms.

# संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन : एनएचआरसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। डराने-धमकाने व आतंक के चलते पीड़ितों में न्याय पाने के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। उन्हें जबरन अवैतनिक श्रम भी करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वहां हिंसा भी हुई थी। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में राज्य की तृणमूल सरकार का नेता शाहजहां शेख आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा था और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी।

आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं।

- बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मानव अधिकार आयोग ने सौंपी अपनी रिपोर्ट
- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

## आयोग की सिफारिशें

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- यौन शोषण पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास मिले
- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापस हो
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन हो
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं
- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाया जाए
- सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाएं
- संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त हो।

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 14.4.2024
Page No. 13, Size:(14.30)cms X (11.62)cms.

# NHRC ने कहा, संदेशखाली में डर से शिकायतें दर्ज नहीं हुईं

■ भाषा, नई दिल्ली

■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर जांच की

**राष्ट्रीय मानवाधिकार** आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में वहां पर आयोग ने अत्याचार की कई घटनाओं को चिह्नित किया। कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बदला लेने के डर और ताकत की वजह से लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई। NHRC ने शनिवार को कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और हर सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ हफ्ते के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने 21 फरवरी को मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लिया था जिनमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में, एक राजनीतिक व्यक्ति के समर्थकों ने महिलाओं को प्रताड़ित कर उनका यौन उत्पीड़न किया।

PUNJAB KESARI, Delhi, 14.4.2024
Page No. 2, Size:(19.46)cms X (16.27)cms.

# मानवाधिकार आयोग ने संदेशखाली पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में 'अत्याचार की कई घटनाओं' को चिह्नित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ''प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया'' जिसने लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने से रोका। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है, ''आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।'' आयोग ने मौके पर पहुंचकर की गई जांच की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ''कथित आरोपी व्यक्तियों के अत्याचारों के कारण बने माहौल ने पीड़ितों को चुप करा दिया और डराने-धमकाने तथा आतंक ने उन्हें न्याय मांगने के प्रति अनिच्छुक बना दिया। उसने यह भी कहा कि ''डर का माहौल'' न केवल पीड़ितों पर असर डालता है बल्कि उन बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी ''नकारात्मक असर'' डालता है जो लगातार इन कथित आरोपियों के हाथों अपने माता-पिता के उत्पीड़न को देखते हैं।

**आयोग ने अपनी जांच में 'अत्याचार की कई घटनाओं' को चिह्नित किया**

PIONEER, Delhi, 14.4.2024
Page No. 3, Size:(34.57)cms X (12.73)cms.

# NHRC flags human rights violations in Sandeshkhali

**PIONEER NEWS SERVICE**
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has flagged, "numerous instances of atrocities," suggesting a clear "violation of human rights" in Sandeshkhali in West Bengal due to "neglect" in preventing such occurrences.

The NHRC report following a spot inquiry into the incident also noted that the "widespread fear of retaliation, compounded by existing power dynamics, acted as a significant obstacle," hindering individuals from expressing their grievances.

The rights panel has put forward several recommendations and has requested an action taken report (ATR) within eight weeks on each recommendation from the West Bengal government, as stated in a statement released by the NHRC on Saturday.

"The Commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The Commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, West Bengal for submitting the ATR.

The NHRC report made an observation that the "atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent", and intimidation, and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who constantly witness the ordeals of their parents at the hands of these alleged accused.

On February 21, the NHRC had taken suo motu cognisance of print and electronic media reports that in Sandeshkhali, North 24th Paragana, "innocent and impoverished women have been harassed and sexually assaulted by a group of local gang of a political person". As a result, for the last few days, local villagers had started protesting, seeking appropriate legal action against the "perpetrators of horrific crimes indulged by various goons and anti-social elements, when the local administration failed to take appropriate legal action against the perpetrators of crime," it added.

In addition to seeking reports from the state government, the Commission, considering the gravity of the situation, had deputed an investigation team for a spot inquiry, headed by one of its members.

"In response, thereto, the DG and IGP, West Bengal vide communication dated 29.02.2024, revealed that a total of 25 cases were registered among which seven cases were on alleged complaints of a sexual offence against women and 24 accused persons were arrested", it said. Efforts were also being made to arrest the absconding perpetrators of the crime. The overall situation of the entire Sandeshkhali police station area and Nazat police station area was described to be "well under control".

The NHRC investigation team found that there is a need to "uproot the fear" of these persons from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride.

It is the duty of the district authorities, being arms of a welfare state, to take consistent measures to instil confidence in the residents of the area in general, and victims in particular, so that others who have been victims of crimes may come forward and file their complaints, the statement said.

The NHRC, in its statement, said its team also interacted with the police and administration at Sandeshkhali and requested for further information, "but despite reminders, no reply has been given to date". The recommendations given by the NHRC team include "reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities" and ensuring witness protection and redressal of grievances.

DAINIK BHASKAR, Delhi, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(13.64)cms X (9.45)cms.

# संदेशखली में आयोग की रिपोर्ट, मौके पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के संकेत

**नई दिल्ली** | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली मामले की मौके पर की गई जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें एनएचआरसी ने 'अत्याचार के कई मामलों" की पहचान करने का दावा किया है। एनएचआरसी पे कहा है कि मौके पर की गई जांच से संकेत मिलता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में 'लापरवाही' के कारण 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ता पक्ष से जुड़े होने से स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाए। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि मानवाधिकार आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और पश्चिम बंगाल सरकार से उनमें से प्रत्येक पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। एनएचआरसी ने 21 फरवरी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया था।

AMAR UJALA, Delhi, 14.4.2024
Page No. 17, Size:(5.24)cms X (6.92)cms.

# आयोग ने कहा, संदेशखाली में हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने दावा किया कि वहां लापरवाही के कारण पीड़ितों के साथ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

संदेशखाली की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 'सत्ता के साथ मिलकर, प्रतिशोध का डर भयानक बाधा के रूप में काम करता है', जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने से रोकता है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं और सभी अनुशंसा पर आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। एजेंसी

फाइल फोटो

## पीड़ित डर के कारण नहीं मांग पाए न्याय

एनएचआरसी ने संदेशखाली की घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। एनएचआरसी ने यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के भूस्वामियों को लौटाना और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं।

ASIAN AGE, Delhi, 14.4.2024
Page No. 4, Size:(4.64)cms X (9.49)cms.

# NHRC probe flags rights violation in Sandeshkhali case

## *Seeks action taken report in 8 weeks*

**New Delhi, April 13:** In a spot inquiry into the Sandeshkhali case in West Bengal, the NHRC has flagged "several instances of atrocities", saying it indicates that there was a "violation of human rights" due to "negligence" in the prevention of such incidents. The National Human Rights Commission, in its report, also observed that the "pervasive fear of reprisal, coupled with the power dynamics at play, acted as a formidable barrier", preventing individuals from voicing their grievances.

The rights panel has made several recommendations and sought an action taken report within eight weeks on each of the recommendations made therein from the government of West Bengal, the NHRC said in a statement on Saturday. "The commission's spot inquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant," it said.

The report has been uploaded on the NHRC website for "wider dissemination of information," the statement said.

The commission has sent its spot inquiry report to the chief secretary and DGP, Bengal for submitting the ATR. The NHRC report made an observation that "atmosphere due to the atrocities by alleged accused persons rendered the victims silent", and terror made them "reluctant to seek justice".

This "climate of terror" not only "perpetuates the cycle of abuse" but also underscores the urgent need to create a safe and supportive environment for victims to "break free from the shackles of silence", it has observed.

The rights panel has also made an observation that the "atmosphere of fear" not only affects the victims but also has a "negative impact" on the growth and health of the children who witness ordeals of their parents at hands of these alleged accused. — *PTI*

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 14.4.2024
Page No. 1, Size:(15.81)cms X (20.84)cms.

# 'संदेशखाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बंगाल के प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के संदेशखाली में मौके का दौरा करने पर पाया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मन में भरोसा जगाने और उनके पुनर्वास व कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर बंगाल सरकार से आठ सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

एनएचआरसी की टीम ने दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आरोपितों द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पीड़ित खामोश हो गए हैं। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेशखाली क्षेत्र और राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और भूमि पर कब्जे के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आयोग सुनवाई में हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर कब्जे के मामले सामने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वहां की महिलाओं ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया था। वहां महिलाओं के यौन शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में पूर्व तृणमूल नेता शेख शाहजहां आरोपित है। वह काफी दिन तक गायब रहा और बाद में उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

मीडिया में आई खबरों पर एनएचआरसी ने लिया था स्वत: संज्ञान पेज>>6

## मीडिया में आई खबरों पर एनएचआरसी ने लिया था स्वत: संज्ञान

प्रथम पृष्ठ से आगे

संदेशखाली प्रकरण की मीडिया में आई खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 21 फरवरी को स्वत: संज्ञान लिया था और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने मौके पर जाकर हकीकत पता लगाने के लिए अपनी एक टीम भी संदेशखाली भेजी थी। आयोग की टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपितों के गैंग से मिलीभगत के कारण लोगों को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन न मिलना, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ या मनरेगा का लाभ न देना या उसमें भेदभाव किए जाने के लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं।

### आयोग की सिफारिशें

- कानून के शासन और अधिकारियों में लोगों का विश्वास बहाल किया जाए
- थाना संदेशखाली क्षेत्र से लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले की जांच हो
- गवाहों की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हो
- यौन शोषण पीड़ितों को परामर्श और पुनर्वास मिले
- भूमि के वैध मालिकों को भूमि वापसी हो
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो
- जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं
- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का संचालन हो
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा किए जाए
- भूमि को पूर्व रूप में लाकर कृषि योग्य बनाया जाए
- सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में सुधार और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाएं
- संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त हो।